सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 80 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 02 जनवरी 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए बनेंगे विश्राम गृह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त 'विश्राम गृह' बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व स्वास्थ्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में मंत्रालय नवा रायपुर में मेडिकल एजुकेशन विभाग और सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के बीच एक एमओयू हुआ।

इस समझौते के तहत इन आश्रय स्थलों के निर्माण, सजावट और उनके रोजमर्रा के संचालन का पूरा जिम्मा संस्था खुद उठाएगी। इन विश्राम गृहों में अपनों की सेवा में लगे लोगों के लिए 24 घंटे सुरक्षा, सीसीटीवी की निगरानी, साफ सुथरा भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहेब, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त रितेश अग्रवाल मौजूद रहे।

पहले चरण में इन शहरों का चयन

योजना के पहले पड़ाव में रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों के मेडिकल कॉलेजों को चुना गया है, जहां दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में लोग उम्मीद लेकर पहुँचते हैं। यह पहल दिखाती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फदवा और डॉक्टर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें उन लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए जो अपने बीमार परिजनों के लिए संबल बनकर साथ खड़े रहते हैं। यह कदम न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि उन हजारों परिवारों को एक बड़ी मानसिक राहत भी पहुंचाएगा जिनके पास शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं होता।

स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार

इलाज सिर्फदवाओं से नहीं, अपनों के साथ और सुकून से भी होता है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को नया विस्तार मिलने जा रहा है। इस एमओयू के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए बेहतर और सुविधाजनक 'विश्राम गृह' बनेंगे जो 'नो प्रॉफिट–नो लॉस' के आधार पर संचालित होंगे।

– श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

परिजनों का ध्यान रखना जरूरी

राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बेहतर इलाज उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों की गरिमा और सुविधा का भी ख्याल रखना है। विश्राम गृहों के माध्यम से मरीज परिजनों को सम्मानजनक आवास, भोजन और बुनियादी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी।

– विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

खास-खबर

राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री साय ने दी नए वर्ष की शुभकामनाएं

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से शुक्रवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और राज्य हित से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर डेका ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

धीरेन्द्र शास्त्री बोले: रामकथा के साथ अब राष्ट्रकथा भी आवश्यक

रायपुर। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री महाराज ने छत्तीसगढ़ की धरती से राष्ट्रकथा अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि आज देश को सिर्फ धार्मिक कथाओं से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने की जरूरत है। प्रभु राम भारत की आत्मा में बसते हैं और जब तक देश एकजुट रहेगा, तब तक कोई शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। ऑपरेशन विजय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के अंतिम दौर से गुजर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसे समाप्त करने का संकल्प ले लिया है और तय समयसीमा के भीतर यह अभियान सफ्ल होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि जवानों के बलिदान और सरकार के दृढ़ संकल्प से 31 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा संभव है।

शहीद आरक्षक की पत्नी को 1.10 करोड़ का चेक

बीजापुर। बीजापुर में शहीद आरक्षक दिनेश नाग की पत्नी पूजा नाग को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत 1.10 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। यह राशि माओवादी विरोधी अभियान में उनकी शहादत के बाद परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है। आरक्षक दिनेश नाग डीआरजी बीजापुर में तैनात थे। वे 18 अगस्त 2025 को माओवादी विरोधी अभियान के दौरान माओवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने सरस्वती शिक्षा संस्थान को दिए चार ई- रिक्शे

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने शुक्रवार को लोकभवन में सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर को चार ई–रिक्शे प्रदान किए। उन्होंने लोकभवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छानुदान मद से चार ई–रिक्शे की चाबी वाहन चालकों को सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में 174 किमी सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्र से मिली 665 करोड़ की मंजूरी

सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गडकरी का जताया आभार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में चार सड़क खंडों के के लिए 664 करोड़ 67 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सीआरआईएफ से प्राप्त होने वाली इस राशि से राज्य के पांच जिलों में करीब 174 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। मंत्रालय ने स्वीकृति का आदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेजा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। इस राशि से मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जैसे दूरवर्ती जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन होगा। इससे राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में परिवहन बेहतर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मुंगेली, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं गरियाबंद जिलों में 664.67 करोड़ की लागत से 173.70 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम साय ने कहा इन सड़कों का कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीण सड़कों नेटवर्क काफी मजबूत होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी।

डबल इंजन सरकार के कारण हो रहा विकास

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़कों का विस्तार हो रहा है। डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज प्रगति पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में नई सड़कों के निर्माण और विद्यमान सड़कों की मजबूती व उन्नयन के लिए विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में 8092 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति जारी की गई है।

प्रोजेक्ट में यहां बनेंगी सड़कें

केंद्र सरकार द्वारा सीआरआईएफसे सुकमा से दंतेवाड़ा मार्ग के 68 किमी लंबाई में टू–लेन सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 230 करोड़ 85 लाख रुपए तथा गरियाबंद जिले में राजिम–फिंगेश्वर–महासमुंद मार्ग में 35.5 किमी लंबाई में सड़क की मजबूती और उन्नयन के लिए 146 करोड़ 86 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इन महत्वपूर्ण मार्गों के विकास एवं उन्नयन से इन जिलों में राज्यीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला मार्ग अच्छी होंगी और आवागमन बेहतर होगा।

आजादी के बाद पहली बार सुकमा के नक्सल प्रभावित गोगुंडा पहुंचा प्रशासन

श्रीकंचनपथ न्यूज

सुकमा। आजादी के बाद पहली बार सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित और दुर्गम नियद नेल्ला नार क्षेत्र के ग्राम गोगुंडा में जिला प्रशासन की टीम ने नए साल की पहली सुबह दस्तक दी। कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में अधिकारियों ने घने जंगलों और कठिन रास्तों को पार करते हुए सुबह 7:30 बजे गांव पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरे का उद्देश्य दूरस्थ अंचलों में शासन की उपस्थिति दर्ज कराना और ग्रामीणों का विश्वास मजबूत करना था।

दौरे के दौरान, अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना और मौके पर ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ग्राम गोगुंडा में ही राशन का भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस भवन की स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करने से मुक्ति मिलेगी। ई–केवाईसी, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए। पेयजल, सड़क, बिजली और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

कर्नाटक सरकार के सर्वे में ईवीएम हुई पास, 70 फीसदी लोगों को भरोसा

बेंगलुरू। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर सर्वे में ईवीएम पर जनता ने मजबूत भरोसा दिखाया है। राज्य सरकार की एजेंसी का सर्वे के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।

सर्वे का शीर्षक 'नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार पर किए गए अंतिम सर्वे का मूल्यांकन' था। इसमें 83.61 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है। कुल मिलाकर 69.39 फीसदी प्रतिभागियों ने माना कि ईवीएम सही नतीजे देती है, जबकि 14.22 फीसदी ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। यह सर्वे 5,100 प्रतिभागियों के बीच 102 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। इसमें बंगलूरू, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूर प्रशासनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया।

विशाखापट्नम की जगह रायगढ़ा में समाप्त व शुरू होगी वंदेभारत एक्सप्रेस

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेयर मंडल के रायगड़ा–विजयनगरम सेक्शन में अपग्रेडेशन कार्य के कारण कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने एवं गंतव्य से पहले समाप्त एवं प्रारंभ का निर्णय लिया। 20829 दुर्ग– विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस दिनांक 5,12 एवं 19 जनवरी, 2026 को दुर्ग से चलकर रायगड़ा में समाप्त होगी। इसी प्रकार 20830 विशाखापट्टनम– दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस दिनांक 05,12 एवं

19 जनवरी, 2026 को विशाखापट्टनम के स्थान पर रायगड़ा से दुर्ग के लिए रवाना होगी। इसके अलावा 58528 विशाखापत्तनम – रायपुर पैसेंजर 5,12,19 जनवरी व 58527 रायपुर– विशाखापत्तनम पैसेंजर 5,12,19 जनवरी 2026 को रद्द रहेगी।

विदेश मंत्री जयशंकर को बलूचिस्तान से मिला खुला पत्र लिखा- पाकिस्तान को उखाड़ फेंको, हम भारत के साथ

इस्लामाबाद ए.। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के निर्वासित बलोच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को एक खुला पत्र लिखा है। इस ओपन लेटर में मीर यार बलोच ने भारत और बलूचिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बताते हुए सहयोग बढ़ाने की अपील की।

बलोच नेता ने भारत के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का दिया हवाला

इस खुले पत्र में एक ओर मीर यार बलोच ने भारत और

बलूचिस्तान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक रिश्तों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत से पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग भी कर डाली। बलोच नेता ने कहा कि इस मामले में बलूचिस्तान का हर नागरिक भारत के साथ है। इस खुले पत्र में बलोच नेता ने लिखा, हिंगलाज माता मंदिर जैसे पवित्र स्थल हमारी साझा विरासत के प्रतीक हैं।

बलोच नेता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफकी और मोदी सरकार की साहसिक और दृढ़ कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने लिखा, बलूचिस्तान के लोग बीते 69 वर्षों से पाकिस्तान का दमन झेल रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंका जाए।

बल्लारी हिंसा : भाजपा विधायक समेत 11 पर एफआईआर

बेंगलुरू। कर्नाटक के बल्लारी में गुरुवार को हुई हिंसा के मामले में भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफ्आईआर दर्ज की गई है। वहीं हिंसा के बाद बल्लारी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी और भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया 'फ्लिहाल स्थिति नियंत्रण में है और अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। हालात अभी शांतिपूर्ण हैं और सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई

भी अवांछित घटना न हो।' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति हथियार लहरा रहा है और हवाई फायरिंग कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता श्रीरामुलु, शेखर, अलिखन और सोमशेखर रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

डिप्टी सीएम साव के ओएसडी विपुल कुमार का ट्रांसफर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव की निजी स्थापना में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर विपुल कुमार गुप्ता को साव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद की जगह उन्हें उनके मूल विभाग/कार्यालय में वापस भेजा गया है। कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी को उपमुख्यमंत्री अरुण साव का ओएसडी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के साथ अजय कुमार त्रिपाठी अब उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में सभी प्रशासनिक और समन्वयात्मक जिम्मेदारियां देखेंगे।

छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, बढ़ेगी ठंड

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के एक–दो जगहों पर बूंदाबांदी होने की

संभावना है। यह बारिश का सिलसिला अगले दो दिनों तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इसके बाद आने वाले अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर फिर से बढ़ जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान दुर्ग संभाग के एक–दो क्षेत्रों में शीतलहर का असर देखा गया। इस दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक तापमान दुर्ग में 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।

संघ प्रमुख ने सिखाया एकता का पाठ

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ब्रिटिश स्वेच्छा से भारत से नहीं गए, हमने उन्हें एकजुटता से भगाया। अपनी एकता और अखंडता के कुछ सूत्रों को हम भूल गए, इसलिए दृष्टि में भेद आ गया था। अंग्रेजों को हमारी एकता अच्छी नहीं लगी, इसलिए भेद पैदा किया। भारत में आकर भी कुछ लोग भारत की रीति में नहीं रहते हैं, इसलिए वह आक्रमण करते हैं। हम चिंतित हैं लेकिन हमें और चिंतित होना चाहिए। हम सब एक दूसरे को पकड़कर चलें। भागवत जी नेक कहते हैं पर लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। भागवत जी को घर–घर में होने वाली बहसों को सुनना चाहिए। प्रवचन पंडालों में जाकर भी बैठना चाहिए। सहकर्मियों के बीच बढ़ते वैमनस्य को भांपना चाहिए। यहां तक कि सेना के एक अधिकारी कह चुके हैं कि जाति–धर्म का भेद सेना के मनोबल को कम कर सकता है। इससे ज्यादा कोई क्या ही कहेगा भला? लोगों का कुतर्क है कि संख्या बल तय करता है कि सच क्या है। हम इसे नहीं मानते। जब पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है तो लोग हंसे। फिर जब अरस्तु ने सिद्ध कर दिया कि धरती गोल है तब भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि जहाज समन्दर में दूर तक जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। आज भी लोग मानते हैं कि ईश्वर और स्वर्ग ऊपर है जबकि धरती के गोल होने को लेकर कोई शंका नहीं है। आप जिधर होते हैं आपका आकाश भी उधर होता है। अर्थात हर तरफ आकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने आस्थागत स्वभाव के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देता है। आज मुट्ठी भर लोग चिंतित हैं कि देश के भीतर भरे जा रहे जहर के कारण लोकजीवन संकट में है। विभाजन की रेखाएं और गहरी होती जा रही हैं। अंग्रेज भी यही तो चाहते थे। देश हथियारों से मजबूत नहीं होता, बल्कि हथियारों को चलाने वाले हाथों से मजबूत होता है। ये हाथ किसी के भी हो सकते हैं। जब बंदूकें देश के भीतर ही एक दूसरे पर तन जाएं तो किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत ही कहां रह जाती है।

छत्तीसगढ़ में ठंड से 22 दिन में दूसरी मौत, पैरावट में मिली लाश

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से लगे श्रीगढ़ में नए साल की रात एक बुजुर्ग की ठंड से मौत हो गई। उसका शव पैरावट में अकड़ा हुआ मिला है और अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। बुजुर्ग के पास से बस का टिकट भी मिला है, जिससे आशंका है कि वह कहीं बाहर से आया था। कम कपड़ों में खुले में सो जाने के कारण वह हाइपोथर्मिया की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। अंबिकापुर में यह ठंड से मौत का दूसरा मामला है। इससे पहले 11 दिसंबर की रात अंबिकापुर बस स्टैंड में खुले में सोए एक व्यक्ति की ठंड से मौत हो गई थी।

संपादकीय

मेहनतकशों की बेकद्री

गिग-वर्कर्स की मांगों को गंभीरता से लें

बाजार आने-जाने के झंझट से बचा लोगों के घरों में तुरत-फुरत जीवन उपयोगी सामान पहुंचाने वाले गिग-वर्कर्स की जटिल कार्यपरिस्थितियां और पसीने का मोल न मिलना, बेहद चिंता की बात है। अपना व परिवार का पोषण करने वाले ये युवा अकसर सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियां चढ़कर ऊंची मंजिलों में दरवाजों तक सामान पहुंचाते देखे जा सकते हैं। बेहद कम मेहनताने, कंपनी मालिकों के दबाव व ग्राहकों की उपेक्षा झेलते गिग वर्कर्स ने नये साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल करके अपनी बदहाली को ही उजागर किया है। संवेदनशील कार्य परिस्थितियों और नौकरी की असुरक्षा के चलते गिग-वर्कर्स हड़ताल पर थे। हालांकि, नये साल पर काम के दबाव व पूरी तरह संगठित न होने के कारण इनकी हड़ताल का कुछ ही इलाकों में असर देखा गया। पूरे देश में सामान की आपूर्ति बाधित हुई हो, ऐसा भी कोई समाचार नहीं मिला है। लेकिन गिग-वर्कर्स की विषम कार्य-परिस्थितियों की ओर पूरे देश का ध्यान जरूर गया है। पिछले दिनों आप के राघव चड्ढा और राजद के मनोज कुमार झा जैसे सांसदों ने गिग वर्कर्स के शोषण का मुद्दा संसद में उठाया था। निस्संदेह, देश की गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन में अपनी क्षमता साबित की है। विडंबना है कि भारत युवाओं को देश का कहा जाता है, लेकिन हम उनकी आकांक्षाओं का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल, गिग-वर्कर्स की प्रमुख मांग है कि उनके काम का बेहतर भुगतान हो और उनके लिये बेहतर कामकाजी परिस्थितियां बनायी जाएं। उनकी इस हड़ताल ने इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा है। लेकिन देश के प्रमुख खाद्य वितरण करने वाली कंपनी ने 31 दिसंबर को इस हड़ताल के बावजूद ऑर्डर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। वहीं थके-हारे बाइकर्स अपनी अनगिनत शिकायतें व्यक्त करते रहे। दरअसल, विडंबना यह है कि खूब काम लेने के बावजूद गिग-वर्कर्स को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी के दायरे से बाहर आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। दरअसल, गिग-वर्कर्स को नई अर्थव्यवस्था में नियोक्ता एक कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के दायित्व से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नियोक्ताओं की हायर व फायर की रणनीति के चलते, वे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में काम करने को बाध्य होते हैं। इसके बावजूद वे आज शहरी जीवन व्यवस्था के लिये अभिन्न अंग बन गए हैं। लोगों की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दौड़ते रहते हैं। वे सामान दस मिनट तक दरवाजे पर पहुंचाने के दबाव में हांफते-भागते, मोटरसाइकिल दौड़ाते और सीढ़ियों पर सामान चढ़ाते अकसर नजर आते हैं। आम तौर पर उपभोक्ताओं का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। देरी होने पर इन्हें झिड़का जाता है। सामान में नुक्स निकालकर इन्हें दौड़ाया जाता है। आज भारत में इनकी संख्या सवा करोड़ से अधिक है।

अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इन कामगारों की संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक हो सकती है। निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि मेहनताने में कटौती, जरा सी चूक पर आर्थिक दंड तथा समय से पहले पहुंचाने के दबाव से गिग-वर्कर्स त्रस्त हैं। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते रहने के बावजूद ये कामगार हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग नहीं ले पाये। दरअसल, प्लेटफॉर्म अकसर प्रोत्साहन और अतिरिक्त वेतन के जरिये श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को दबा देते हैं। निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तरह औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर के टर्नओवर का एक से दो फीसदी सामाजिक सुरक्षा कोष में अनिवार्य योगदान और आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर को कानूनी मान्यता की दिशा में एक लंबे समय से प्रतीक्षित बदलाव का संकेत देते हैं। हालांकि, कार्यान्वयन ही यह निर्धारित करेगा कि ये सुधार परिवर्तनकारी साबित होते हैं या केवल प्रतीकात्मक रहते हैं।

“ निश्चित रूप से गिग-वर्कर्स का लगातार 14 घंटे काम करने के बावजूद सात-आठ सौ रुपये कमाना और दुर्घटना बीमा से वंचित रखना, इस व्यवस्था की उन खामियों की ओर भी इशारा करता है, जिन्हें केवल फौरी लालच या प्रोत्साहन से ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में हालिया श्रम सुधारों का महत्व बढ़ जता है। जिसमें पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानून के तरह औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है।

अदावत को दोस्ती में बदलने की कूटनीतिक पहल

पुष्परंजन

विश्लेषकों ने माना है, कि एस. जयशंकर को ढाका भेजने का फैसला कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। एस. जयशंकर ढाका जितने समय थे, उन्होंने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मिलने की ज़हमत नहीं उठाई। जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने भारतीय राजनयिकों के साथ मुलाक़ात की बात मानी है। यह ख़बर जंगल में आग की तरह फैली है। बांग्लादेश स्थित जमात-ए-इस्लामी को भरोसे में लेने की ज़रूरत और भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर का पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के जनाजे में शामिल होना, ये दो घटनायें सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को असहज किये हुए है। मोहम्मद यूनुस चुनाव तक बांग्लादेश में बतौर 'गेस्ट आर्टिस्ट' हैं, बाद के दिनों में वो राष्ट्रपति बनेंगे, या मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे? यह सवाल अधर में लटका पड़ा है। रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में, जमात अमीर ने कहा कि जब मैं बीमार था, जैसे दूसरे देशों के राजनयिक मुझसे मिलने आए, वैसे ही दो भारतीय राजनयिक भी कुशल-क्षेम के वास्ते मेरे घर आए थे। मैंने उनसे वैसे ही बात की, जैसे दूसरों से की थी।

जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा, 'भारतीय राजनयिकों ने अनुरोध किया कि इस दौरे को सार्वजनिक न किया जाए। आगे भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय हितों से जुड़ी भविष्य की कोई भी बैठक की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।' जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने पुष्टि की, कि मैंने अपनी बाईपास सर्जरी के बाद सितम्बर, 2025 की शुरुआत में एक भारतीय राजनयिक से मुलाकात की थी। अब सवाल यह है, कि क्या जमात लीडरशिप बीएनपी नेताओं के सम्बन्ध भारत के साथ सॉफ्ट करने में कोई भूमिका निभा रही है? यह भी एक क़िस्म की 'पोलिटिकल बाईपास सर्जरी' है, जिससे मुहम्मद यूनुस के रणनीतिकार अनजान थे।

जमात ने आखिरी बार 2001 और 2006 के बीच बीएनपी के साथ एक जूनियर गठबंधन सहयोगी के रूप में सत्ता संभाली थी, और वह फिर से उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। बाहर से यही दिख रहा था कि भारत विरोधी माहौल बनाने में जमात पाकिस्तान के इशारों पर यह सबकुछ कर रहा था, लेकिन अब वो क्यास कथा पलटती दिख रही है।

बांग्लादेश में हिन्दू विरोधी माहौल से देश, और देश से बाहर किस-किस को फायदा मिलता है? इस बारे में डिप्लोमेट तो खुलकर बोलेंगे नहीं, लेकिन यह विश्लेषण का विषय है। बुधवार को, जिस तरह का हुजूम बेग़म ख़ालिदा ज़िया के जनाजे में दिखा, वो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) एक बार फिर सियासी पारी खेल सकती है। सबका यही अनुमान था कि चुनाव तक बांग्लादेश में जो पार्टियां मैदान में हैं, वो हिन्दुओं को निशाने पर लेते हुए, भारत विरोधी विष वमन करेंगी। लेकिन, किसी ने सोचा नहीं था कि इस बीच बीएनपी की सर्वोच्च नेता ख़ालिदा जिया को सिपुर्द-ए-खाक़ करने की सूरत बन आएगी, और भारतीय विदेशमंत्री शोक और दोस्ती का पैगाम लेकर ढाका जायेंगे। विश्लेषकों ने माना है, कि एस. जयशंकर को ढाका भेजने का फैसला कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक है। एस. जयशंकर ढाका जितने समय थे, उन्होंने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मिलने की ज़हमत नहीं उठाई। इससे साफ़ संदेश जा रहा था, कि भारत सरकार की दिलचस्पी देश के अस्थायी व्यस्थापक में कतई नहीं है। पीएम मोदी अदावत को दोस्ती में बदलने की कला में माहिर राजनेता हैं। उसका एक और उदाहरण बुधवार को देखने को मिल गया। जून, 2015 में बांग्लादेश यात्रा के दौरान, मोदी ने खालिदा ज़िया से मुलाकात की, जो उस समय विपक्ष की नेता थीं। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक बताया, मोदी ने बाद में इसे एक 'गर्मजोशी भरी मुलाकात' के रूप में याद किया। उसी मुलाक़ात का हवाला मोदी के पत्र में था, जो उनके बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को अपने विदेशमंत्री के माध्यम से भेजा था।

बांग्लादेश से भारत के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव वाले ही रहे हैं। सैन्य शासन के पंद्रह साल की अवधि के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने एक-दूसरे को बड़े पैमाने पर सुरक्षा अनिश्चितता की दृष्टि से देखना शुरू किया था। दोनों देशों ने एक-दूसरे के क्षेत्र में विद्रोहियों को गुप्त समर्थन दिया। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में शांति वाहिनी का समर्थन किया। इस बीच, ढाका ने भारत के उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों को हथियारों की खेप पहुंचाने में मदद की, और उन्हें बांग्लादेशी धरती पर शिविर स्थापित करने की अनुमति दी।

ज़िया की बीएनपी सरकार को भी भारत विरोधी ही माना जाता था। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन के साथ रक्षा सौदों को बढ़ावा दिया गया, जो भारत के लिए चिंता का विषय था। उन्होंने भारतीय ट्रकों के लिए बांग्लादेश से होकर जाने वाले ट्रांजिट को 'गुलामी' बताया और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत को ट्रांजिट अधिकार देने से इनकार कर दिया। खालिदा जिया पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों को पनाह देने, और आईएसआई के साथ सांठगांठ के आरोप लगे। बेग़म ज़िया ने 1972 की भारत-बांग्लादेश मैत्री संधि और 1996 की गंगा जल संधि को 'गुलामी की संधि' और 'गुलामी का सौदा' करार दिया था। सबके बावजूद, शेख हसीना से दोस्ती के पुराने दिन याद करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो नई दिल्ली के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं।

इस बार अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात, बांग्लादेश में भारत के लिए अवामी लीग के रूप में कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति में जो विकल्प दिखते हैं, उन्हीं के साथ भारत को संबंध दुरुस्त करने होंगे। डिप्लोमेटिक सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं, कि भारतीय राजनयिकों ने लंदन प्रवास के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान के साथ अनौपचारिक संपर्क बना रखा था। इसलिए एस. जयशंकर का ढाका जाना, आपदा में अवसर जैसा ही था।

बीएनपी नेता तारिक़ रहमान के लन्दन से लौटने के बाद, जितनी तेज़ रफ्तार से सियासी मौसम में बदलाव आया है, उससे मुहम्मद यूनुस की सरपरस्ती वाले छात्र नेता असमंजस में हैं। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 28 फरवरी, 2025 को नेशनल सिटीजन पार्टी की स्थापना की थी। नाहिद की नेशनल सिटीजन पार्टी सत्ता में आने के सपने देखने लगी थी। संभवत: इनके लिए ही मुहम्मद यूनुस ने दिसंबर के बदले दो माह आगे चुनाव टाल दिया था। कहने को जमात से जुड़ा 'इस्लामी छात्र शिबिर' के नेता अबू शादिक 'कायेम' और बीएनपी के छात्र नेता रकिबुल इस्लाम राकिब भी आंदोलन में परिचित चेहरे थे। एक और छात्र संगठन 'इंकलाब मंच' के सह-संस्थापक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद, बीएनपी ने इनके घावों पर मरहम लगाना शुरू किया है। ऐसे में लगता नहीं कि छात्र नेता किसी लीड रोल में नमूदार होंगे।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सार्वजनिक सुनवाई से डरती राजनीतिक पार्टियां

विनीत नारायण

किसी भी लोकतंत्र में, सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, ऐसे अधिकारियों को बुलाने, उन्हे जवाबदेह बनाने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं, जो जनता की ओर से होता है। इससे भ्रष्टाचार, दुरुपयोग या नीतिगत असफलताओं पर रोशनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पटेल की सुनवाई से एपस्टीन फाइलों पर जनता को जानकारी मिली, जो अन्यथा छिपी रह सकती थी।

अमेरिका की व्यवस्था और राजनीति में हाल फिर एक ऐसी घटना घटी जब एफबीआई निदेशक काश पटेल को कांग्रेस की हाउस ज्यूडिशियरी कमिटी ने तलब किया। दिसंबर 2025 में ही उनसे जवाब तलब हुआ। पटेल को जेफरी एपस्टीन फाइलों, एफबीआई की पारदर्शिता और अन्य विवादास्पद मुद्दों पर अमेरिकी सांसदों ने कड़े सवाल किए। सुनवाई के दौरान एक एपस्टीन वीडियो चलाया गया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। पटेल ने दावा किया कि एपस्टीन की फाइलों में इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि उन्होंने अन्य लोगों को ट्रैफिकिंग की गई पीड़िता महिलाएं प्रदान की थी। और जांच पुराने गैर-अभियोजन समझौतों से बंधी हुई है।

उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने ही एपस्टीन के खिलाफ मामले को खोला था जबकि पहले के प्रशासन (ओबामा और बाइडेन) ने फाइलें जारी नही कीं। डेमोक्रेट सांसदों ने पटेल पर ट्रंप को बचाने का आरोप लगाया, जबकि पटेल ने इनकार किया। उन्होने कहा कि सभी कानूनी रूप से जारी करने योग्य जानकारी साझा की जा रही है। सुनवाई में एजेंटों की पुनर्नियुक्ति, चार्ली किर्क की हत्या की जांच और एफबीआई के राजनीतिकरण जैसे मुद्दे भी उठे, जहां पटेल ने अपराध दर में कमी और गिरफ्तारियों में वृद्धि का हवाला दिया।

यह सुनवाई अमेरिकी लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता को दर्शाती है। कांग्रेस याकि संसद द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराना वहां परंपरा है। काश पटेल, जो ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं और एफबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त हुए, को सितंबर 2025 में भी सीनेट और हाउस कमिटियों के समक्ष भी पेश होना पड़ा था। लेकिन दिसंबर की सुनवाई अधिक विवादास्पद रही क्योंकि इसमें एपस्टीन स्कैंडल पर फोकस था। सुनवाई के दौरान सांसदों ने पटेल से सीधे सवाल किए, जैसे एपस्टीन फाइलों में ट्रंप का नाम कितनी बार आया और क्यों रेडैक्शन (संशोधन) के लिए लगभग 1,000 एजेंटों को लगाया गया।

पटेल ने इनकार किया कि संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और कहा कि जांच चल रही है, लेकिन अदालती आदेशों से बंधे हैं। इस तरह की सुनवाई लाइव प्रसारित होती हैं, जो जनता को सीधे देखने का अवसर देती हैं और यह अमेरिकी संविधान की जांच और संतुलन की व्यवस्था का हिस्सा है।

यदि तुलना की जाए तो भारत में भी यों संसद द्वारा किसी अधिकारी को बुलाने की प्रक्रिया है। लेकिन यह अमेरिकी कांग्रेस की तरह सार्वजनिक और जवाबदेही में सख्त नहीं होती। भारतीय संसद की स्थायी समितियां, जैसे लोक लेखा समिति (पीएसी), अनुमान समिति या संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी), अधिकारियों को बुला सकती हैं और पूछताछ कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में जेपीसी ने अधिकारियों को समन किया था, लेकिन ये कार्यवाहियां बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, मीडिया को अनुमति नहीं होती और कोई लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता।

अमेरिका में जहां सुनवाई टीवी पर लाइव होती है और सांसद अधिकारियों को कड़े सवाल भी कर सकते हैं, भारत में यह गोपनीय रहती है ताकि जांच प्रभावित न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के तहत समितियां स्वतंत्र हैं, लेकिन सार्वजनिक सुनवाई की परंपरा नहीं है।

क्या भारत में कभी ऐसी सुनवाई हो सकती है? यह संभव है, लेकिन राजनीतिक घोटालों के बावजूद राष्ट्रपति प्रणाली में व्यवस्था का चैक-बैलेंस है। जबकि यहां प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए अधिकारी को बुलाना मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठा सकता है, जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। यदि कोई बड़ा घोटाला हो, जैसे राफेल डील या कोयला घोटाला आदि, तो जेपीसी तो अवश्य बन सकती है, लेकिन सार्वजनिक सुनवाई से राजनीतिक पार्टियां डरती हैं क्योंकि इससे संसद में हंगामा, इस्तीफे या सरकार गिरने का खतरा होता है।

हालांकि, डिजिटल युग में पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है। यदि संसद नियमों में संशोधन करे, जैसे सुनवाई को लाइव प्रसारित करने का प्रावधान, तो यह संभव हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक संस्कृति में, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसी सुनवाई से घोटाला ही फूट सकता है, जैसे संसद में अवरोध या मीडिया ट्रायल। फिर भी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह विचारणीय है।

किसी भी लोकतंत्र में, सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों न हो, ऐसे अधिकारियों को बुलाने, उन्हे जवाबदेह बनाने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है। चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकारी अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं, जो जनता की ओर से होता है। इससे भ्रष्टाचार, दुरुपयोग या नीतिगत असफलताओं पर रोशनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में पटेल की सुनवाई से एपस्टीन फाइलों पर जनता को जानकारी मिली, जो अन्यथा छिपी रह सकती थी। भारत में यदि ऐसा हो, तो सरकारी योजनाओं या जांचों की पारदर्शिता अवश्य बढ़ेगी।

दूसरा, यह जांच और संतुलन की व्यवस्था को मजबूत करता है। लोकतंत्र में कोई भी शाखा निरंकुश नहीं होनी चाहिए। विधायिका द्वारा कार्यकारी को बुलाना सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सत्ता में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, यह प्रक्रिया नीतियों को जनहित में रखती है। तीसरा, जनता की भागीदारी बढ़ती है। सार्वजनिक सुनवाई से लोग सूचित होते हैं, जो मतदान और सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करता है। चौथा, यह राजनीतिक पार्टियों को पारदर्शी बनाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को अपनी नीतियों का बचाव करना पड़ता है, जबकि विपक्ष को रचनात्मक सवाल करने पड़ते हैं। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधरती है।

भारतीय खेलों का निर्णायक क्षण

राहुल बोस

2025 भारत के खेलों के लिए एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। यह साल सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत के खेल तंत्र में बड़े बदलाव शुरू हुए। सरकार और निजी क्षेत्र ने खेलों में निवेश बढ़ाया, नई नीतियां बनाई गई और खेल सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब इन कदमों को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि भारत खेलों में मज़बूत और सफल राष्ट्र बन सके। इस साल सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दी। यह नीति भारतीय खेलों के लिए एक लंबी अवधि की सोच और बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का लक्ष्य तय करती है। भारत पहले ही 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा भी जताई है।

इसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 लागू किया गया। इस कानून ने खेल प्रशासन की व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। अब फैसले मनमर्जी से नहीं, बल्कि पारदर्शी तरीके और तय नियमों के अनुसार होंगे। इस कानून में खिलाड़ियों को केंद्र में रखा गया है। चयन प्रक्रिया, फंडिंग से जुड़े फैसले और शिकायत निवारण जैसी चीजों के लिए साफ नियम, मानक और समय-सीमा तय की गई है।

इससे अनियमितता कम होगी और खिलाड़ियों, खासकर छोटे शहरों और कम सुविधाओं वाले पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ियों के बीच भरोसा बढ़ेगा। मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि पहली बार इस कानून के तहत खेल संगठनों को अनिवार्य रूप से एक सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी अपनानी होगी, ताकि महिलाओं, नाबालिग खिलाड़ियों और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक आचार संहिता भी लागू करनी होगी। एक स्वतंत्र नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और विशेष स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल निगरानी रखेंगे, जिससे स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी। वहीं, खिलाड़ियों की भागीदारी और महिलाओं को निर्णय लेने वाली समितियों में शामिल करना, खेल संघों में शक्ति संतुलन को बेहतर बनाता है। इन सभी बदलावों से खेल व्यवस्था में निष्पक्षता, भरोसा और लंबी अवधि की स्थिरता आएगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है। वे खिलाड़ियों और टीमों को अपने घर बुलाकर सिर्फ सम्मान ही नहीं देते, बल्कि उनसे खुलकर बातचीत भी करते हैं। इन मुलाकातों में खिलाड़ियों की जीवन यात्रा, उनकी चुनौतियाँ, त्याग और सफलताओं पर बात होती है। मैं भी अलग-अलग खेलों में भारत की प्रगति को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ। इसी महीने जोशना चिनप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह ने इतिहास रचा, जब भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता।

भारतीय महिलाओं ने 2025 में दुनिया के खेल मंच पर शानदार प्रदर्शन किया। नवंबर 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीता। इसी तरह, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी अपनी पहली टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा।

मुक्केबाज़ी में भी भारत ने शानदार शुरुआत की और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में नौ स्वर्ण पदक जीते। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भी भारत ने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में हुए एशिया कप 2025 में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीता और आठ साल बाद फिर से एशियाई चैम्पियन बनी।

18 साल की शीतल देवी पैराआर्चरी में विश्व चैंपियन बनीं, और दिव्या देशमुख पहली भारतीय महिला बनीं जिन्होंने फाइड महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता।2025 में भारत की खेल सफलताएँ सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों तक फैलीं। हाल ही में एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप तमिलनाडु में हुआ, और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल ग्रेटर नोएडा में आयोजित किए गए। अहमदाबाद में बने नए और विश्वस्तरीय वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित हुई। रग्बी में भी बड़ी उपलब्धि देखी गई। बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर-20 सेवन टूर्नामेंट हुआ, जिसमें भारतीय महिला टीम ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशिया रग्बी के अध्यक्ष क़ैस अल धलाई ने कहा कि बिहार में इस तरह का बड़ा युवा रग्बी टूर्नामेंट होना न सिर्फ खेल का जश्न है, बल्कि पूरे एशिया में खेल के फैलते विकास का मजबूत प्रमाण भी है।

कई मायनों में रग्बी की प्रगति भी भारत के बड़े खेल बदलाव का ही हिस्सा है। जून 2025 में मुंबई में पहली बार रग्बी प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ। यह दुनिया की शुरुआती फ्रेंचाइज़ी आधारित रग्बी सेवन्स लीगों में से एक है। इसमें छह शहरों की टीमें (जैसे चेन्नई बुल्स, हैदराबाद हीरोज़, मुंबई ड्रीमर्स आदि) शामिल थीं, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिजी और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े रग्बी देशों के 30 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी भी खेले। 15 जून को मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए पहले मैच में बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ देखने आए। मैच टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव दिखाए गए। चार-चौथाई वाले रोमांचक मैच फॉर्मेट ने नई पीढ़ी के दर्शकों को आकर्षित किया और यह भरोसा दिलाया कि रग्बी भी भारत के व्यावसायिक खेलों का हिस्सा बन सकता है।

इससे यह साफ दिखता है कि रग्बी कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि सिर्फ एक महीने बाद भारत ने बिहार के राजगीर जैसे शहर में एशियाई स्तर की रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी भी की। केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत कई शहरों में अलग-अलग खेलों के लिए फ्रेंचाइज़ी आधारित लीग शुरू करने की बड़ी योजना बनाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अस्मिता (स्स्ड्ढञ्ज) महिला रग्बी लीग ने देश के कई शहरों में युवा लड़कियों के बीच रग्बी को काफी बढ़ावा दिया है। साथ ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। टीवी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म खेलों के प्रसारण अधिकार ले रहे हैं और स्पॉन्सर भी अब भारतीय खेलों को एक मजबूत और फायदेमंद अवसर के रूप में देखने लगे हैं।

इस साल युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मिलने वाली मदद की योजना में बड़े बदलाव किए। अब फेडरेशंस के लिए फंड पाने के लिए साफ नियम तय किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, जिन फेडरेशंस का वार्षिक बजट 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें अब एक फुल-टाइम हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर रखना ज़रूरी है, जो खेल की तकनीकी और प्रदर्शन से जुड़ी योजनाओं को संभाले। हर खेल संगठन को अपने बजट का कम से कम 20त्न हिस्सा जमीनी स्तर के विकास, यानी जूनियर और युवा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर खर्च करना होगा, और कम से कम 10त्न हिस्सा कोच और सपोर्ट स्टाफ की ट्रेनिंग पर लगाना होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के संभावित खिलाड़ियों को अब नॉन-कैम्प दिनों में भी 10,000 रुपये मासिक डाइट भत्ता दिया जाएगा, ताकि कोई खिलाड़ी आर्थिक कमी की वजह से खाना छोड़कर अपने सपने पूरे करने से पीछे न रह जाए। इसी बीच फिट इंडिया आंदोलन, खासकर सन्डेज ऑन साइकिल पहल (दो बार मैं खुद हिस्सा रहा हूँ), पूरे देश में लोगों को हर हफ्ते साइकिल चलाने और फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह पहल केंद्रीय खेल मंत्री ने शुरू की है और भारतीयों में शारीरिक फिटनेस बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूँगा-खेल और फिटनेस समाज की जीवनशैली का हिस्सा बनने चाहिए। तभी असली और टिकाऊ बदलाव आएगा।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
भिलाई–दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

नववर्ष पर स्वच्छता दीदीयों एवं कर्मियों का सम्मान

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में नववर्ष पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय को अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों एवं मैदानी सफाई कर्मियों वार्ड पार्षद एवं निगम के कर्मचारियों की उपस्थिति में पुष्प देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पर्यावरण को बचाना है प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है का नारा लगाते हुए जन जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए विशेष बैठक

भिलाई। नगर पालिक निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आगामी सर्वेक्षण के विभिन्न मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष का स्वच्छ सर्वेक्षण 12,500 अंकों का है। सर्वेक्षण में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए केवल निगम की टीम पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें शहरवासियों का विशेष योगदान और सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। कचरा कलेक्शन रिक्शा सभी घरों में एक निर्धारित समय पर पहुँचेंगे। शत-प्रतिशत घरों से कचरा उठाव सुनिश्चित किया जाए। स्रोत पर गीला सूखा पृथक्कीकरण आवश्यक है। प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध पर जोर दिया गया।

पाटन में राजिम भक्तिन माता की जयंती 8 को, कुंभ नगरी राजिम से जुड़ा है इतिहास

श्रीकंचनपथ समाचार

पाटन। राजिम भक्तिन माता की जयंती महोत्सव समारोह की तैयारियों को लेकर परिक्षेत्रीय साहू संघ अरसनारा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 8 जनवरी को ग्राम देमार में आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए परिक्षेत्रीय अध्यक्ष किशन हिरवानी के निर्देश पर सभी इकाइयों में बैठकें हुई। उल्लेखनीय है कि राजिम में भी यह महोत्सव जोर-शोर से मनाया जाता है। तैलिक समाज की भक्तिन माता में गहरी आस्था है।

महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के संगम स्थल पर हर साल माघी मेला लगता है। राजिम शैव और वैष्णव परंपरा का संगम स्थल है। राजिम के इस पवित्र स्थल में ही भगवान श्रीराम ने कुलेश्वर महादेव की स्थापना कर उनकी पूजा-अर्चना की थी। राजिम नगरी छत्तीसगढ़ का प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है। यहां से प्रवाहित होने वाली

महानदी पापमोचिनी गंगा कहलाती है। क्षेत्र में राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है। राजिम में भक्तिन माता जयंती 7 जनवरी मनाई जाती है। कलचुरी राजा जगपाल देव द्वारा 1145 में स्थापित शिलालेख में माता का उल्लेख मिलता है। एक दंतकथा के अनुसार इस स्थान का नाम 'राजीव' या 'राजिम' नामक एक तैलिक स्त्री के नाम से हुआ था. कुलेश्वर मंदिर के भीतर स्थित 'सतीचौरा' का संबंध भी इन्हीं से जुड़ा है।

उस दौर में तैलिय वंश के लोग इस क्षेत्र में तिलहन की खेती करते थे। तैलिक धर्मदास और उनकी पत्नी शांतिदेवी दोनों विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी बेटी का नाम राजिम था। राजिम मूर्ति विहीन राजीवलोचन मंदिर में जाकर प्रतिदिन पूजा करती थी। भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते ही वे पूरे क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। कालांतर में उनकी पूजा एक देवी के रूप में की जाने लगी। माता के दर्शन करने प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं।

स्कूल के वार्षिकोत्सव में आकर ताजा हो जाती हैं बचपन की ढेर सारी यादें - बघेल

दिव्य अनुभूति विद्यालय में भावुक हो गए दुर्ग सांसद

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। दिव्य अनुभूति विद्यालय कोहका के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने कहा कि वार्षिक उत्सव में इतना अपनापन होता है कि अपने बचपन की याद आ जाती है। इस दौरान जिंदगी में कोई चिंता नहीं होती, केवल उत्साह उमंग और तरंग होता है।

सांसद ने कहा, दिव्य अनुभूति का मतलब ही एक संस्कारिक स्कूल है जहां विगत 25 वर्षों से बच्चों को उच्च शिक्षा देकर यहां के बच्चे कई प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

समारोह को भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष बृजेश भोजपुरिया और महेश वर्मा ने भी संबोधित किया द्वय नेताओं ने कहा कि निश्चित रूप से जय प्रकाश घनघोरकर जी बच्चों को अच्छा संस्कारी के छात्र बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं।

भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने कहा कि हम सभी जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में ही शिक्षा एवं संगठन में काम करने के लिए उनसे प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में काम किया निश्चित रूप से स्कूल के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय है भिलाई त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है भारत... जहां बच्चे-बच्चे में राम और घर-घर बसती सीता है...

जहां अनेक धर्म और संस्कृति की एकता विश्व में मिशाल है। विश्व गुरु के इस धरती पर ऋषि-मुनियों के संस्कार हिलोरी मारती है... यही देखने को मिला दिव्य अनुभूति विद्यालय, चांदनी चौक, कोहका के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में।

इस अवसर पर स्कूल की अनेक गतिविधियों में सालभर श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अतिथियों ने पुरस्कार प्रदान किए।

संचालन प्राचार्य माधुरी वर्मा व प्रभारी अन्नपूर्णा ने किया। अतिथियों में बृजेश बिजपुरिया भाजपा भिलाई, पूर्व जिला अध्यक्ष, संयोजक महेश वर्मा, संगठन प्रभारी, अमित मिश्रा, भाजपा आईटी प्रदेश सह संयोजक, निशिकांत शर्मा, संजय जे. दानी, स्वीटी कौशिक, अध्यक्ष, महिला मोर्चा, डॉ. प्रदीप चौधरी, जिला संयोजक, चिकित्सा प्रकोष्ठ, भिलाई दुर्ग, ब्रजकिशोर द्विवेदी, भाजपा जिला संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ, दुर्ग, शारदा गुप्ता, उपाध्यक्ष, भाजपा भिलाई इस्पात मजदूर संघ, कन्हैया लाल सोनी, अध्यक्ष, व्यापारी संघ, कोहका सुरेश मालवीय जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ भाजपा अशोक यादव शैलेंद्र वर्मा व भानु जंघेल उपस्थित थे।

वीर बालक ओम उपाध्याय का किया सम्मान

समारोह के मंच पर खास अवसर रहा कि राज्य के वीर बालक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से 'साहिबजादा अजीत सिंह' अवार्ड से सम्मानित, दिव्य अनुभूति विद्यालय में ग्यारहवीं का छात्र ओम उपाध्याय को उनकी वीरता और साहस के लिए सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल और शिक्षाविद् स्कूल संचालक जेपी घनघोरकर, महेश वर्मा संगठनन प्रभारी भाजपा कवर्धा ने शाल-श्रीफल, मैडल और स्मृति चिन्ह से ओम का अभिनंदन किया।

विधायक की मकर संक्रांति भेंट अब सिर्फ एक रुपए में एक्स-रे

मुफ्त ब्लड टेस्ट की सुविधा का हजारों ले रहे लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। वैशाली नगर विधानसभा के रहवासी अब 14 जनवरी से मात्र 1 रूपये में एक्स-रे करवा सकेंगे। एमएलए रिकेश सेन ने जीरो रोड शांति नगर स्थित विधायक कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया है।

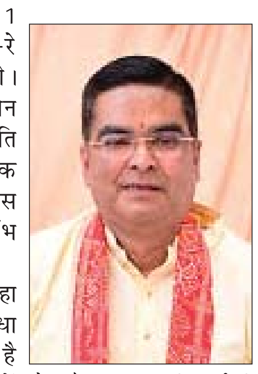

श्री सेन ने कहा कि एक्स-रे सुविधा अत्यंत जरूरी है क्योंकि यह हड्डियों के फ्रैक्चर, मोच, गठिया और जोड़ों के विस्थापन संक्रमण (जैसे निमोनिया), ट्यूमर, दांतों की समस्याओं और शरीर के अंदर निगली गई वस्तुओं का तुरंत, गैर-आक्रामक और सटीक निदान करने में मदद करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों को सही उपचार योजना बनाने और उपचार की प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलती है। इससे अनगिनत जानें बचती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक लगातार विकास के साथ ही सभी को सहज स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके इस प्रयास में हाल ही में उन्होंने विधायक कार्यालय में नि:शुल्क ब्लड टेस्ट सुविधा प्रारंभ की है जिसका हर रोज सैकड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। ब्लड सैंपल से 31 तरह के टेस्ट की रिपोर्ट लोगों को दी जा रही है।

विधायक रिकेश सेन ने कहा कि एक्स-रे आधुनिक चिकित्सा का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बिना सर्जरी के शरीर के अंदर देखने और सटीक निदान करने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के आंकलन के साथ ही और शरीर में फंसी हुई वस्तुओं को खोजने, स्तन कैंसर और अन्य प्रकार के ट्यूमर का पता लगाने में एक्स-रे हम सभी के जीवन में जरूरी है।

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के रहवासी सेवा का लाभ लेने विधायक कार्यालय से मात्र 1 रूपये की टोकन राशि देकर 14 जनवरी से सुबह 8 से 11 बजे तक एक्स-रे करा सकेंगे।

सेवानिवृत्ति पर कार्मिकों को बीएसपी ने दी भावभीनी विदाई

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र की सेवा से दिसंबर 2025 माह में कुल 91 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसमें खदान बिरादरी के 08 सदस्यों सहित 12 कार्यपालक व 71 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

कार्यपालकों हेतु विदाई समारोह का आयोजन इस्पात भवन स्थित निदेशक प्रभारी सभागार में 31 दिसंबर 2025 को किया गया। निदेशक प्रभारी चित्त रंजन महापात्र ने कार्यपालकों को सेवानिवृत्ति आदेश प्रदान किया तथा उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें स्वस्थ एवं सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशकगण अजय कुमार चक्रवर्ती, प्रवीण निगम, पवन कुमार, प्रबीर कुमार सरकार, राकेश कुमार, सीएमएलओ कमल भास्कर तथा सीएमएलओ अरुण कुमार उपस्थित रहे।

श्री महापात्र ने सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से आत्मीय संवाद कर संयंत्र के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में उनके अनुभव और सुझाव आमंत्रित किए। जिन पर निदेशक प्रभारी एवं कार्यपालक निदेशकों ने विस्तार से चर्चा की। सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों ने अपने कार्यकाल की यात्रा साझा करते हुए अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त किया। कार्यपालक निदेशकों ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को नए पड़ाव के लिए अपनी शुभकामनाएँ दीं।

सेवानिवृत्त होने वालों में सुब्रत मुखोपाध्याय, संदीप माथुर, सुशील कुमार, गोविंद त्र्यंबकराव दांडेगांवकर, प्रशांत तिवारी, महाराणा प्रताप सिंह, मनोज कुमार, अमरेश कुमार, रमेश कुमार अग्रवाल, राजेश कमार सिंह, तनवीर अहमद तथा प्रबंधक यतीन्द्र पुरंग शामिल हैं।।

भिलाई निवास में संयंत्र के गैर-कार्यपालकों को भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ के ठाकुर, एवं डीजीएम एचआर जेएन ठाकुर और डीजीएम एचआर राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति आदेश प्रदान किया।

नए साल के साथ ही बीएसपी में सुरक्षा माह प्रारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्त रंजन महापात्र ने नववर्ष के प्रथम दिवस इस्पात भवन परिसर में सुरक्षा ध्वज फहराकर संयंत्र बिरादरी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं तथा 'सुरक्षा जागरूकता माह-2026' का औपचारिक शुभारंभ किया।

श्री महापात्र ने सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों से सुरक्षित कार्य संस्कृति को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुरक्षा ऑडिट शेड्यूल वार्षिक कैलेंडर-2026 का विमोचन भी किया गया। कैलेंडर में चित्रित सुरक्षा पोस्टरों के कलाकारों की सराहना की गई।

जीएम सुरक्षा अभियांत्रिकी एस. सुनोव द्वारा सुरक्षा शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण अजय कुमार चक्रवर्ती, प्रवीण निगम, पवन कुमार, पीके सरकार, राकेश कुमार, कमल भास्कर, अरुण कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. विनीता द्विवेदी सहित संयंत्र के विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी, मुख्य महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

श्री महापात्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि संयंत्र के विभिन्न विभागों, इकाइयों एवं परियोजना क्षेत्रों में कार्यरत सभी नियमित एवं ठेका श्रमिकों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी कर्मी के जीवन की कीमत पर उत्पादन नहीं चाहते। हमारी सजगता, अनुशासन एवं सतर्कता ही संयंत्र की सुरक्षा का मूल मंत्र है। सुरक्षित कार्य प्रणाली के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्घटना मुक्त उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 'सुरक्षा संस्कृति – सुरक्षा आज, कल और अनवरत' के सिद्धांत को अपने दैनिक कार्य व्यवहार में आत्मसात करना होगा।

छत्तीसगढ़ी हाना लोकज्ञान, भाषा और चित्रकला का अनूठा संगम

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। छत्तीसगढ़ी हाना का हिंदी भावार्थ एवं संबंधित चित्र/तस्वीर निर्माण पर आधारित अंतर-महाविद्यालयीन प्रतियोगिता का आयोजन इंटैक दुर्ग-भिलाई अध्याय द्वारा स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय के सहयोग से किया गया।

इंटैक दुर्ग भिलाई अध्याय की संयोजिका डॉ हंसा शुक्ला ने कहा कि इंटेक का उद्देश्य विद्यार्थियों को सांस्कृतिक धरोहर से परिचित करना है तथा हाना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर एवं भाषा के समृद्धि का प्रतीक है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ी भाषा की समृद्ध लोकपरंपरा, लोकज्ञान और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना तथा उन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति संवेदनशील बनाना था। प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को हाना का हिंदी भावार्थ प्रस्तुत करने के साथ-साथ उससे संबंधित चित्र या दृश्यात्मक अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान किया गया, जिससे भाषा के साथ-साथ उनकी सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रतिभा भी विकसित हो सके।

डॉ सुनीता वर्मा विभागाध्यक्ष हिंदी कार्यक्रम प्रभारी ने बताया नई शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में रखने पर विशेष बल दिया गया है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण-अधिगम अधिक सहज, प्रभावी और संस्कारपूर्ण बनता है। छत्तीसगढ़ी हाना जैसी लोकविधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ अत्यंत आवश्यक हैं, इनके माध्यम से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ती है।

निर्णायक के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार सरला शर्मा पद्मनाभपुर एवं स.प्रा, शिक्षा विभाग उषा साहू उपस्थित रहीं।

विजयी प्रतिभागियों को इंटैक दुर्ग-भिलाई अध्याय के सौजन्य से पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की अदिति पांडे, द्वितीय स्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की एकता दीवान तथा तृतीय स्थान स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की नंदिनी कर एवं रिया बोरकर को दिया गया। सांत्वना पुरस्कार संदीपनी इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी की रेणुका साहू को प्रदान किया गया।

डॉ. सुनीता वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने अतिथियों, निर्णायकों, प्रतिभागियों तथा आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सड़क सुरक्षा एवं स्वच्छता हेतु अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाएगा बीएसपी प्रबंधन

भिलाई। टाउनशिप क्षेत्र में सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता एवं शहरी स्वच्छता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अनाधिकृत होर्डिंग्स एवं प्रचार सामग्रियों को हटाने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। जनवरी 2026 के प्रथम पखवाड़े में टाउनशिप के प्रमुख मार्गों, सड़क किनारों एवं चौराहों के आसपास अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाने की विशेष कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के अंतर्गत रोड किनारे एवं चौक-चौराहों पर स्थापित अनाधिकृत बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स तथा उनसे उत्पन्न अपशिष्ट सामग्रियों को हटाया जाएगा। संबंधित सभी संस्थाओं, संगठनों एवं राजनीतिक/सामाजिक दलों से अपील की गई है कि यदि उनके द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्रचार सामग्री इन क्षेत्रों में लगाई गई है, तो वे उसे स्वेच्छा से तत्काल हटा लें, ताकि उनकी सामग्रियों को संभावित क्षति से बचाया जा सके। निर्धारित अवधि के पश्चात, प्रवर्तन दल, पुलिस टीम एवं नगर निगम की संयुक्त टीम इन्हें बलपूर्वक हटा दिया जाएगा।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

छत्तीसगढ़ की प्रमुख नृत्य एवं लोक कला, संस्कृति पर फोटो प्रदर्शनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति, पारंपरिक नृत्यों और विविध लोक कलाओं को जनसमुदाय तक पहुँचाने के लिए क्लाउड एवं संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ के सहयोग से एक विशेष फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी राज्य की जनजातीय, ग्रामीण और लोक परंपराओं की जीवंत, कलात्मक और प्रामाणिक झलक प्रस्तुत करेगी, जो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त रूप से दर्शाती है। प्रदर्शनी 2 से 4 जनवरी तक कला वीथिका, महंत घासीदास परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।

नगर घड़ी चौक में घड़ी का तकनीकी सुधार कार्य शीघ्र

रायपुर। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राजधानी शहर रायपुर में नगर घड़ी चौक में स्थापित नगर घड़ी का संधारण कार्य किया जा रहा है. नगर घड़ी में आवश्यक तकनीकी सुधार कार्य करने आवश्यक पाट्र्स रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक पाट्र्स को छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से मंगवाया गया है। आवश्यक पाट्र्स अगले 2-3 दिवस में आने के उपरांत शीघ्र नगर घड़ी का संधारण कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत महासमुंद में नया आईजी रेंज

रायपुर। प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू कर दी जाएगी। इसके लिए अब 6 हजार फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नए दफ्तर की तलाश शुरू हो गई है। महासमुंद में नया आईजी रेंज बनाना होगा तथा ए-डीसीपी कोर्ट लगाएंगे जहां पर विभिन्न धाराओं के आरोपियों की सुनवाई होगी। बजट सत्र में पुलिस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा वहीं कमिश्नर कार्यालय के लिए नया आफिस बनाना पड़ेगा। सिविल लाईन में यहां पर ए-डीसीपी भी बैंठेगे। फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। वर्तमान में 2750 को फोर्स उपलब्ध है जिसे बढ़ाकर 6 हजार फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। पहले आरोपियों को एसडीएम के कोर्ट में पेश किया जाता था। अब इन्हें ए-डीसीपी की कोर्ट में पेश करना होगा।

प्रसूति पर मिलेगा मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ

मोहला। श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति के दौरान मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना है। यह लाभ पंजीकृत महिला श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों हेतु दिया जाता हैं। योजना के तहत 20 हजार रूपए का लाभ मंडल में 1 वर्ष पूर्व से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को बच्चे के जन्म के 90 दिवस भीतर आवेदन करने पर दिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिक अनिवार्य रूप से बनवाएं आयुष्मान वय वंदन कार्ड

मोहला। जिले के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की अपील की है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ बीपीएल एवं एपीएल दोनों श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान रूप से लागू है। योजना की विशेषता यह है कि यदि किसी परिवार में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक से अधिक सदस्य हैं, तो प्रत्येक पात्र सदस्य को अलग-अलग 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ शासकीय एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिक अपना कार्ड अस्पताल में प्रस्तुत कर सकते हैं।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बना गिद्ध संरक्षण का केन्द्र, जीपीएस ट्रैकिंग एवं 'वल्चर रेस्टॉरेंट'

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। मध्य भारत के सबसे स्वच्छ नदी-वन पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल यह रिजर्व अब केवल बाघों और जंगली भैंसों का ही नहीं, बल्कि विलुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार इंद्रावती के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण कर इनकी घटती आबादी को बचाना और बढ़ाना है। गिद्ध पर्यावरण के 'सफाईकर्मी' हैं और इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। गिद्धों के अस्तित्व पर जहरीली दवाओं, असुरक्षित शव निपटान और मानव हस्तक्षेप जैसे गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित निगरानी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें उच्च-रिजॉल्यूशन गिद्ध गतिविधि डेटा का उपयोग संरक्षण कार्यों की दिशा तय करने के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों से पता चला है कि गिद्ध लगभग 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और घने जंगलों व मानव बस्तियों के बीच आनाजाना करते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 से गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पहली बार दो गिद्धों की सैटेलाइट ट्रैकिंग से 18,000 से अधिक जीपीएस डेटा पॉइंट्स प्राप्त किए गए हैं। जीवविज्ञानी सूरज कुमार के नेतृत्व में गिद्ध मित्र दल की अहम भूमिका रही है। यह दल घोंसलों की निगरानी, शवों के सुरक्षित प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी सामुदायिक सहयोग से 'गुड्डा सारी गुट्टा' जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहली बार निर्बाध प्रजनन सुनिश्चित हो सका है। उप-निदेशक संदीप बलागा के पर्यवेक्षण में वल्चर रेस्टोरेंट की स्थापना भी की गई है।

हेल्थ केयर में कौशल विकास हेतु सत्य साईं हेल्थ एवं एजुकेशन के साथ एमओयू

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के विकास को मिलेगी गति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह एमओयू राज्य में हेल्थकेयर क्षेत्र का दायरा बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करने तथा युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

समझौते का मुख्य उद्देश्य हेल्थकेयर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, युवाओं का कौशल उन्नयन तथा आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे।

एमओयू के तहत चार प्रकार के कोर्स संचालित किए जाएंगे, जिनमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन, कार्डियक केयर तकनीशियन तथा इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन के प्रशिक्षण शामिल हैं। ये कोर्स युवाओं को विशेषज्ञता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर निर्माण का अवसर उपलब्ध कराएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास को विकास की रीढ़ मानती है और विशेष रूप से हेल्थकेयर सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलयुक्त कार्यबल तैयार करने पर बल दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ युवाओं के लिए व्यापक रोजगार संभावनाएँ भी उत्पन्न करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कौशल विकास पर केंद्रित यह साझेदारी राज्य के दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी। प्रशिक्षित युवा अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थानों और आपातकालीन सेवाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सी. श्रीनिवास सहित ट्रस्ट के प्रतिनिधि एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कोकोड़ी एथनॉल प्लांट से बढ़ी किसानों की आमदनी

श्रीकंचनपथ समाचार

कोण्डागांव। माँ दंतेश्वरी मक्का सहकारी समिति कोण्डागांव द्वारा संचालित एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी क्षेत्र के शेयरधारक किसानों के लिए आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम साबित हो रहा है। प्लांट से जुड़े किसानों को मक्का विक्रय पर बाजार भाव की तुलना में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। एथेनॉल प्लांट के संचालन के बाद समिति द्वारा शेयरधारक किसानों से प्राथमिकता के आधार पर मक्का की खरीद की जा रही है। इस वर्ष भी किसानों को मक्का का बेहतर मूल्य देकर उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में खुले बाजार में मक्का का भाव 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी द्वारा शेयरधारक किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की आकर्षक दर पर मक्का की खरीद की जा रही है। इससे किसानों को बाजार भाव की तुलना में सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। बाजार भाव 1600 रूपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्लांट दर 2400 रूपए प्रति क्विंटल है, अतिरिक्त लाभ 800 प्रति क्विंटल है। उदाहरण के तौर पर 40 क्विंटल मक्का विक्रय पर किसान को कुल अतिरिक्त आय 32 हजार रूपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। स्थानीय किसानों ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जुड़ने के बाद खेती अधिक लाभकारी बनी है। 800 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती में उत्साह बढ़ा है। यह लाभांश आर्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान मक्का उत्पादन से जुड़ सकें।

हसदेव नदी के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट निर्माण की मांग'

कोरबा। नमामि हसदेव सेवा समिति ने कोरबा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी के दोनों किनारों पर दर्री बांध से कुदुरमाल पुल तक रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। यह कदम हसदेव नदी के प्रदूषण को कम करने, इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने और नदी के तट पर सुविधाओं के निर्माण के उद्देश्य से उठाया गया है। समिति का मानना है कि रिवर फ्रंट निर्माण से ना केवल पर्यावरणीय सुधार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। हसदेव नदी की महत्ता को देखते हुए समिति ने दर्री बांध से कुदुरमाल पुल तक रिवर फ्रंट निर्माण का प्रस्ताव दिया है ताकि नदी के किनारों को साफ किया जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इससे नदी के संरक्षण के साथ ही नदी से जुड़ी संस्कृति और पारिस्थितिकी को बचाने का एक गंभीर प्रयास भी है।

'प्रगति' प्लेफार्म से बीएसपी और लारा संयत्र को मिली नई ऊर्जा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की गति नई ऊँचाइयों पर पहुँची है। दशकों से लंबित महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं ऊर्जा परियोजनाएँ अब 'प्रगति' प्लेटफॉर्म के माध्यम से समयबद्ध ढंग से पूरी हो रही हैं। यह केंद्र की परिणामोन्मुख, जवाबदेह तथा निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 'प्रगति' का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से न केवल देश में रेल उत्पादन को नई गति मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिली है और औद्योगिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है।

इसी प्रकार एनटीपीसी की लारा सुपर थर्मल पावर परियोजना (1600 मेगावाट) से छत्तीसगढ़ सहित छह राज्यों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है तथा औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'प्रगति' ने परियोजनाओं की निगरानी, निरंतर समीक्षा और बाधाओं के त्वरित समाधान की एक सशक्त प्रणाली विकसित की है। स्पष्ट लक्ष्य, तेज़ क्रियान्वयन और ठोस परिणाम—यही नए भारत की कार्यसंस्कृति है और यही 'विकसित भारत - 2047' के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति की 50वीं बैठक ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को भी नई गति प्रदान की है।

प्रगति सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए विकसित एक आईसीटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसने परियोजनाओं की निगरानी और समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। पिछले दशक में प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की रफ्तार तेज हुई है। इससे देशभर में अवसंरचना, ऊर्जा, रेल, सड़क, कोयला और अन्य क्षेत्रों से जुड़े अनेक कार्यों को समयबद्ध प्रगति मिली है। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

कलेक्टर और एसपी ने किया धान खरीदी का निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बलरामपुर जिले में कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था का कलेक्टर और एसपी ने आज संयुक्त रूप से विकासखंड कुसमी के विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों तथा चेकपोस्टों का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा एवं पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने विकासखंड कुसमी अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र चांदो एवं सामरी का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक से चर्चा कर टोकन व्यवस्था, अब तक की गई धान खरीदी की मात्रा तथा धान उठाव की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। किसी भी स्थिति में बिचौलियों एवं कोचियों द्वारा धान विक्रय न होने पाए।

कलेक्टर ने बारदानों की उपलब्धता, स्टेंसिल सही स्थान पर अंकित करने तथा निर्धारित मात्रा में ही धान भरने के निर्देश दिए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। धान का शीघ्र उठाव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तराजू, नमी मापक यंत्र, बारदाना पंजी एवं खरीदी पंजी की जांच कर उनका समुचित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर ने धान खरीदी केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अवैध धान परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग लेने के निर्देश दिए।

खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में खुला डायलिसिस केन्द्र

श्रीकंचनपथ समाचार

खैरागढ़। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सिविल अस्पताल खैरागढ़ में 3 बिस्तरों वाली डायलिसिस यूनिट संचालित की जा रही है। यहां 3 आधुनिक डायलिसिस मशीनों स्थापित किये गये हैं।

मार्च 2025 से प्रारंभ सेवा में प्रतिमाह 30 डायलिसिस सेशन किए जा रहे हैं। वर्तमान में 09 सक्रिय केस नियमित रूप से उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

इस डायलिसिस यूनिट का मुख्य उद्देश्य जिले के मरीजों को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराना है। यूनिट में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों एवं प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस सुविधा के शुरू होने से अब जिले के नागरिकों को डायलिसिस जैसे महंगे उपचार के लिए निजी अस्पतालों या अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और आर्थिक बोझ दोनों में कमी आएगी।

डायलिसिस से संबंधित मरीज अथवा हितग्राही मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से अथवा स्वयं सिविल अस्पताल खैरागढ़ में उपस्थित होकर जांच एवं उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतिक्रमण मुक्त वन क्षेत्र में सागौन रोपने का प्रयोग सफल

12 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए लगभग 30 हजार रूटशूट पौधे

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य में वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार अतिक्रमण मुक्त वन क्षेत्र में सफल वृक्षारोपण किया जा रहा है। राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक प्रेमकुमार ने विगत शनिवार को कवर्धा परियोजना मंडल के अंतर्गत सिंघारी परिक्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने कक्ष क्रमांक 419 में किए गए द्वितीय वर्ष के सागौन वृक्षारोपण का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की और मौके पर उपस्थित अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रबंध संचालक ने वर्ष 2024 में लगभग 12 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए करीब 30 हजार सागौन रूटशूट पौधों की बेहतर स्थिति देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र पहले अतिक्रमण से प्रभावित था, जिसे मुक्त कराकर सागौन का वृक्षारोपण किया गया। मात्र दो वर्षों में पौधों की ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक पहुंच चुकी है। बिना किसी फेंसिंग के पौधों को सुरक्षित रखने और वृक्षारोपण को सफल बनाने में स्थानीय स्टाफद्वारा किए गए प्रयासों की उन्होंने प्रशंसा करते हुए टीम को बधाई दी।

निरीक्षण के दौरान प्रबंध संचालक ने वृक्षारोपण के वैज्ञानिक मूल्यांकन और बेहतर प्रबंधन के लिए निर्देश दिए। उन्होंने पूरे क्षेत्र को प्रति 3 हेक्टेयर के सेक्टर में विभाजित करने, प्रत्येक सेक्टर में शत-प्रतिशत गणना सुनिश्चित करने तथा 0.1 हेक्टेयर के सैंपल प्लॉट बनाकर पौधों की औसत ऊंचाई, गोलाई और वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का नियमित संकलन करने को कहा। साथ ही प्रत्येक तीन माह में जीवित पौधों की संख्या का आकलन कर वृक्षारोपण पंजिका में दर्ज करने तथा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए।

गहन निगरानी के उद्देश्य से प्रबंध संचालक ने स्थानीय प्रजाति के बांस की करील से एक हेक्टेयर क्षेत्र में विशेष परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आगामी रोपण सत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सागौन रूटशूट तैयार करने हेतु केवल स्वस्थ मदर ट्री से बीज और रूटशूट चयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

हरदी बाजार और सरईश्रृंगार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, मुआवजा होगा 'शून्य'

कोरबा। एसईसीएल दीपका परियोजना के विस्तार में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए हरदी बाजार और सरईश्रृंगार क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। कोल धारक अधिनियम की धारा 9 के प्रकाशन के बाद भी प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे अवैध निर्माणों को देखते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत के कड़े निर्देशों पर यह सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अधिग्रहित भूमि पर धारा 9 के बाद किए गए निर्माणों के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार हरदी बाजार अभिजीत राजभानु, राजस्व अमला, पुलिस बल और एसईसीएल अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दोनों गांवों में व्यापक कार्रवाई की। हरदी बाजार क्षेत्र में 55 निर्माणाधीन मकानों पर नोटिस चस्पा कर निर्माण कार्य रुकवाया गया, जबकि सरईश्रृंगार में 29 अवैध ढांचों को चिन्हित किया गया। चेतावनी दी गई कि यदि निर्माण कार्य जारी रहा, तो निर्माण सामग्री जब्त कर दी जाएगी।

विजय देवरकोंडा की नए साल की पोस्ट में दिखीं रश्मिका मंदाना

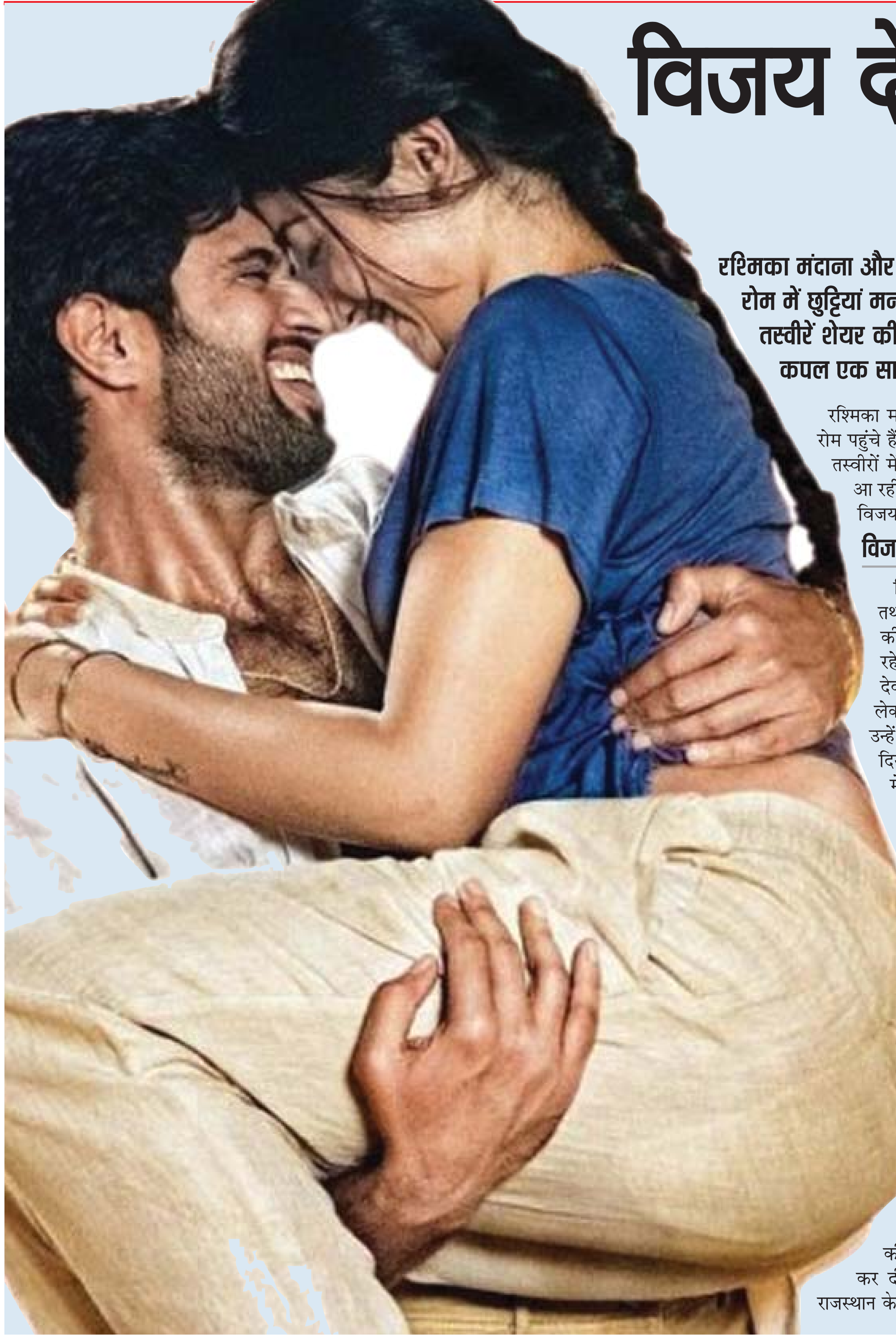

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा नए साल के मौके पर रोम में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। फैंस कयास लगा रहे हैं तथाकथित कपल एक साथ छुट्टियां मनाने निकला है।

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा नए साल के मौके पर रोम पहुंचे हैं। दोनों ने यहां से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। उनकी तस्वीरों में रोम की पुरानी इमारतें और कई दूसरी जगहें नजर आ रही हैं। फैंस ने नोटिस किया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक ही जगह की तस्वीरें शेयर की हैं।

विजय की पोस्ट में दिखीं रश्मिका

विजय देवरकोंडा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनकी तथा कथित पार्टनर रश्मिका मंदाना पहले ही उन जगहों की तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों एक-साथ छुट्टियों पर निकले हैं। विजय देवरकोंडा की तस्वीरों पर फैंस ने रश्मिका मंदाना को लेकर कमेंट किए हैं। एक यूजर ने दावा किया है कि उन्हें विजय की एक फोटो के रिफ्लेक्शन में रश्मिका दिखीं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक दूसरे इमेज में रश्मिका ने एक्टर विजय को पीछे से पकड़ा है। फ्रेम में उनके दोस्तों का रिएक्शन भी दिख रहा है।

रश्मिका ने रोम से शेयर कीं तस्वीरें

इससे पहले रश्मिका मंदाना ने रोम से अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में वह अपने दोस्तों के साथ पोज दे रही थीं। उन्होंने कई ऐतिहासिक इमारतों की भी तस्वीरें शेयर की थीं। विजय देवरकोंडा की तस्वीरों में भी रोम की ऐतिहासिक इमारतें नजर आई हैं।

जल्द ही शादी कर सकता है कपल

खबरों के मुताबिक 3 अक्तूबर 2025 को रश्मिका और विजय ने हैदराबाद में सगाई की थी। इस समारोह में दोनों के परिवार और कुछ खास दोस्त ही मौजूद थे। हालांकि कपल ने खुद सोशल मीडिया पर कोई घोषणा नहीं की, लेकिन बाद में विजय की टीम ने सगाई की पुष्टि कर दी थी। खबरें हैं कि कपल 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में शादी करेगा।

नए साल पर पवन कल्याण के फैंस को मिला तोहफा, सच हुआ मेकर्स का सपना; नई फिल्म की हुई घोषणा

पावरस्टार कहे जाने वाले पवन कल्याण के आंध्र प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनने के बाद फैंस को लगा था कि वो फिल्मों से दूरी बना लेंगे। बीच में ऐसी खबरें भी आई थीं। लेकिन अब 2026 की शुरुआत के साथ ही पवन कल्याण के फैंस को तोहफा मिला है। मेकर्स ने उनकी फिल्म की घोषणा की है।

पवन कल्याण ने नए साल की शुरुआत नई फिल्म से की है। निर्माता राम तल्लूरी ने नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2026 को इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में राम ने बताया है कि पवन कल्याण ने सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित और वक्कंथम वामसी द्वारा लिखित एक फिल्म साइन की है। राम तल्लूरी ने एक्स पर लिखा, 'मेरा सपना जैथरा रामा मूवीज के बैनर तले प्रोडक्शन नंबर 1 के रूप में साकार हो रहा है। हमारे प्रिय पावर स्टार (पीएसपीके) द्वारा प्रेम और आशीर्वाद से इसका नामकरण किया गया है। सुरेंद्र रेड्डी और वक्कंथम वामसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। सदा आभारी। सदा गौरवान्वित। यह ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है।

वक्कंथम वामसी ने भी जताई खुशी

इसके अलावा वक्कंथम वामसी ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, 'यह सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर ही नहीं है, बल्कि सबसे खुशहाल नया साल है। एकमात्र पवन कल्याण के साथ इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं।'

2025 में रिलीज हुई थीं दो फिल्में

इससे पहले साल 2025 में भी पवन कल्याण की दो फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। इनमें पहली फिल्म 'हरि हर वीर मल्लु' थी और दूसरी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' थी। 'हरि हर वीर मल्लु' जहां बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और फ्लॉप रही थी। वहीं 'दे कॉल हिम ओजी' को दर्शकों ने पसंद किया था। अब 2026 के पहले ही दिन पवन कल्याण ने अपनी नई फिल्म की घोषणा करके फैंस को तोहफा दिया है।

प्रभास-तृप्ति स्टारर 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक रिवील

नए साल पर संदीप रेड्डी वांगा का फैंस को तोहफा, इंटेंस लुक में नजर आए दोनों एक्टर

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म के इस ऑफिशियल पोस्टर में प्रभास और तृप्ति डिमरी का लुक रिवील किया गया है। दोनों एक्टर का काफी इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्टर को शेयर करते हुए फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी।

वहीं, फिल्म के मेकर्स ने स्पिरिट पोस्टर को शेयर आते हुए लिखा- 'आइए नए साल का स्वागत जोश से भरे स्पिरिट के पहले पोस्टर के साथ करें। आपने पहले से मौजूद चीजों को पसंद किया। अब उन चीजों से प्यार करें जिनके अस्तित्व के बारे में आप कभी नहीं जानते थे।'

पोस्टर में प्रभास और तृप्ति एक विंडो के पास खड़े दिख रहे हैं। प्रभास लंबे बालों, घनी दाढ़ी और मूंछों के साथ शर्टलेस नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी पर चोट का निशान और कंधे, बांह और पीठ पर कई पट्टियां बंधी हुई हैं। प्रभास के होठों के बीच एक सिगरेट है और एक हाथ में शराब का गिलास है।

वहीं, तृप्ति हल्के ग्रे रंग की साड़ी में प्रभास के करीब खड़ी नजर आ रही हैं और वो प्रभास का सिगरेट जलाती दिखाई दे रही हैं। तृप्ति का फेस काफी शांत और गंभीर नजर आ रहा है। बता दें कि इस फिल्म में संदीप पहले दीपिका पादुकोण को लेना चाहते थे। लेकिन 2024 के सितंबर में जब दीपिका मां बनी उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट की डिमांड की। इसके अलावा उन्होंने हफ्ते में बस 5 दिन काम करने और ज्यादा फीस की डिमांड की थी। एक्ट्रेस की इन सारी मांगों से डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा खुश नहीं थे।

उन्होंने दीपिका की मांगों को अनप्रोफेशनल बताते हुए फिल्म में उन्हें तृप्ति डिमरी से रिप्लेस कर दिया।

म्यूजिकल प्रोजेक्ट में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी अलीजेह अग्निहोत्री, ऑस्कर विजेता फिल्म का है रीमेक

साल 2014 में रिलीज हुई फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' का हिंदी रीमेक बनने वाला है। खबर है कि निर्माताओं ने इस म्यूजिकल फिल्म के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी और अलीजेह अग्निहोत्री को कास्ट किया है। फिल्म का निर्देशन विकास बहल करने वाले हैं। इसकी शूटिंग जून से अगस्त के बीच शुरू हो सकती है।

क्या है 'ला फैमिली बेलियर' की कहानी?

'ला फैमिली बेलियर' एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशक एरिक लार्टिगाउ हैं। इसकी कहानी 16 साल की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। लड़की अपने मूक-बधिर माता-पिता की देखभाल करती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसके म्यूजिक टीचर को उसकी खूबसूरत गाने की आवाज का पता चलता है। लड़की को अपने सपने को पूरे करने और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच चुनाव करना होता है। 'ला फैमिली बेलियर' ने 2022 में 94वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) में बेस्ट पिक्चर का अवॉर्ड जीता था।

ओरिजिनल फ्रेंच की रीमेक होगी फिल्म

पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से लिखा है 'सिद्धांत चतुर्वेदी और अलीजेह अग्निहोत्री की एक फिल्म है, जिसे विकास बहल डायरेक्ट करेंगे। यह बेहतरीन फिल्म होगी। यह एक फ्रेंच फिल्म 'ला फैमिली बेलियर' का रीमेक है, जिसका रीमेक बनाया जाएगा। इस फिल्म ने ऑस्कर जीता था। यह एक म्यूजिकल फिल्म है, यह संजय लीला भंसाली की 'खामोशी' जैसी है। हमने इसे ओरिजिनल फ्रेंच फिल्म से लिया है।'

सिद्धांत-अलीजेह का काम

सिद्धांत चतुर्वेदी को आखिरी बार 2025 की फिल्म 'धड़क 2' में तृप्ति डिमरी के साथ देखा गया था। सिद्धांत चतुर्वेदी जल्द ही मृणाल ठाकुर के साथ फिल्म 'दो दीवाने सहर में' नजर आने वाले हैं। अलीजेह अग्निहोत्री ने साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'फर्रे' से एक्टिंग में डेब्यू किया था। यह उनकी आखिरी फिल्म भी है।

सर्दियों में चोक हो गया है गला, खाने-पीने में भी हो रही है दिक्कत? बड़े काम के हैं ये देसी उपाय

आयुर्वेद चिकित्सा में कई ऐसी प्रभावी औषधियों का जिक्र मिलता है जिनको प्रयोग में लाकर सर्दी-खांसी और गले में खराश से जल्द आराम पाया जा सकता है। सर्दी-खांसी और गले में खराश की समस्या काफी सामान्य है, मौसम में बदलाव या फिर एलर्जी की स्थिति में इस तरह का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

गले में होने वाली इस तरह की दिक्कतों के चलते कुछ भी खाने-पीने और यहां तक कि बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। ज्यादातर मामलों में गले में खराश की दिक्कत को बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होने वाली समस्या के तौर पर जाना जाता है, ऐसे में एंटीबायोटिक्स लेकर इसे ठीक किया जा सकता है। पर हर छोटी-छोटी परेशानी के लिए दवाई खाना ठीक नहीं है। कुछ आसान से घरेलू और आयुर्वेदिक चिकित्सा के उपायों की मदद से भी इसमें लाभ पाया जा सकता है।

आयुर्वेद चिकित्सा में कई ऐसी प्रभावी औषधियों का जिक्र मिलता है जिनको प्रयोग में लाकर सर्दी-खांसी और गले में खराश से जल्द आराम पाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि इसके लिए किन उपायों को प्रयोग में लाना असरदार होता है?

हल्दी-नमक के गरारे

गले के संक्रमण और दर्द को कम करने के लिए हल्दी-नमक के पानी से गरारे करने को भी आयुर्वेद में फायदेमंद पाया गया है। इसके लिए 250 मिली पानी में 1 टेबल स्पून हल्दी और आधा टेबल स्पून नमक डालकर 5 मिनट तक उबालें। इस पानी से गरारे करने से गले की समस्याओं को कम करने में लाभ मिलता है। हल्दी एंटी-इंफ्लामेटरी होती है जो सूजन कम करके दर्द से राहत दिलाने में काफी मददगार है।

शहद से मिलता है आराम

शहद का सेवन करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको गले में खराश की समस्या है तो शहद में काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इससे गले की खराश में आराम मिलता है। वायरल इंफेक्शन से बचाने और इंफ्लामेशन की समस्या को कम करने में शहद का सेवन करके आराम पाया जा सकता है। शहद को आयुर्वेदिक चिकित्सा में कई प्रकार से लाभकारी पाया गया है।

तुलसी का काढ़ा पिएं

तुलसी का काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ गले के संक्रमण को ठीक करने का प्रभावी उपचार हो सकती है। गले की खराश और दर्द को ठीक करने में इससे विशेष लाभ पाया जा सकता है। आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ही गुणकारी बताया गया है। इसका काढ़ा बनाने के लिए एक कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च और 5-6 तुलसी के पत्ते डालकर उबालें। इस पानी को छान कर सेवन करें। गले की खराश और सर्दी जुकाम में इससे लाभ मिलता है।

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस से एकत्रित जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है।

खास खबर

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती : चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित

रायपुर । छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणी जारी कर दी गई है। भर्ती समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह सत्यापन प्रक्रिया भर्ती केंद्र ङ्क 4वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना, जिला रायपुर में आयोजित की जाएगी। जारी कार्यक्रम के मुताबिक सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने पद और रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि पर प्रात: 8 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 फरवरी 2026 तक चलेगी। समय-सारणी के अनुसार मेल नर्स पद के अभ्यर्थियों का सत्यापन 12 और 13 जनवरी 2026 को किया जाएगा। फीमेल नर्स पद के लिए यह प्रक्रिया 14 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक चलेगी। वहीं लैब टेक्नीशियन पद के उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन 22 जनवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। फार्मासिस्ट पद के लिए 23, 27, 28 और 29 जनवरी 2026 को दस्तावेजों की जांच होगी। नर्सिंग असिस्टेंट और ड्रेसर पद के अभ्यर्थियों का सत्यापन 30 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि कम्पाउंडर पद के उम्मीदवारों को 2 फरवरी 2026 को बुलाया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेश पत्र संबंधित तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं उनकी प्रतियों के साथ उपस्थित हों।

सूरजपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हुआ आगाज

सूरजपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत् नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने हेतु प्रेरित करने, दुर्घटना से बचाव के उपाय से लोगों को अवगत कराने, यातायात नियमों की जानकारी सहित यातायात संबंधी विविध आयोजन सड़क सुरक्षा माह के दौरान सूरजपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी। सूरजपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ गुरूवार, 1 जनवरी 2026 को कलेक्टर एस. जयवर्धन व डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर की मौजूदगी में स्कूली छात्राओं के द्वारा हेलमेट रैली और यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरभर में कलेक्टर व डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर ने जवानों के साथ बाईक पर हेलमेट जागरूकता रैली निकालकर नगरवासियों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने सशक्त संदेश दिया। कलेक्टर सूरजपुर एस. जयवर्धन ने कहा कि नागरिकों को अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें, हम सभी के जागरूक होने, नियमों के पालन करने से सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी, हर व्यक्ति की जान काफी कीमती है, बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित रहे। यातायात नियम केवल निर्देश नहीं हैं, बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित दैनिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना रोकने में आपकी जागरूकता ही हमारा सहयोग है। इस अवसर पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह दिनांक 1 से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा।

नारियल का कचरा बना कमाई और पर्यावरण संरक्षण का जरिया

नई दिल्ली(पीआईबी)। एक समय उपभोग का एक अनचाहा उप-उत्पाद रहा कचरा, बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण के साथ एक गंभीर चुनौती बन गया था। भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के आह्वान पर अमल करते हुए स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नेतृत्व और एसबीएम-यू के तहत कचरा अब समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन बन गया है, जिसे उत्पादों और आय में परिवर्तित किया जा रहा है। यह बदलाव तटीय शहरों में सबसे अधिक हुआ है, जहां नारियल का कचरा-जो बड़ी समस्या हुआ करता था - अब चक्रीय अर्थव्यवस्था में एक नया जीवन पा चुका है, जिससे प्रकृति के अवशेषों को आजीविका और मूल्य में परिवर्तित किया जा रहा है।

नारियल का कोई भी छिलका पीछे नहीं छूटेगा: एसबीएम-यू 2.0 के तहत, नारियल का कचरा आजीविका का साधन बन रहा है - तटीय शहर इसे मजबूत रस्सियों और समृद्ध जैविक खाद में परिवर्तित कर रहे हैं।

स्वच्छ, सुरक्षित और खूबसूरत पर्यटन स्थलों की तलाश में पर्यटक तटीय शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और नारियल पानी समुद्र तट पर सबसे पसंदीदा पेय बना हुआ है—यह स्वास्थ्यवर्धक, ताजगी भरा और बेहद लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता के कारण कभी नारियल के कचरे का ढेर लैंडफिल में जमा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज नारियल के कचरे को अलग किया जाता है। पुनर्चक्रित किया जाता है और उसका नया उपयोग किया जाता है—जैविक खाद और मिट्टी के विकल्प के रूप में कोकोपीट में परिवर्तित किया जाता है और नारियल के रेशों से मजबूत रस्सियां बनाई जाती हैं जो कभी समुद्र तट की समस्या थी, वह अब एक स्मार्ट समाधान बन गई है।

नारियल का कचरा अब महज 'हरित अपशिष्ट' से एक बहुमूल्य संसाधन में तब्दील हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शहरी गीले कचरे में नारियल के छिलके का हिस्सा 3-5 प्रतिशत होता है - कागज़ पर तो यह कम लगता है लेकिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 1.6 लाख टन नगरपालिका कचरे के मुकाबले यह बहुत अधिक है, जो तटीय शहरों में बढ़कर 6-8 प्रतिशत तक हो जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल नारियल उत्पादन में अग्रणी हैं - और कर्नाटक अब शीर्ष स्थान पर है - भारत यह साबित कर रहा है कि एक बेकार छिलका भी बड़ा आर्थिक मूल्य प्रदान कर सकता है।

भारत की नारियल उत्पादन की कहानी वैश्विक स्तर पर धूम मचा रही है। नारियल विकास बोर्ड और कॉयर बोर्ड के अनुसार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत योगदान के साथ वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल उत्पादन 21,000 मिलियन यूनिट से अधिक हो गया। इस तरह अपशिष्ट से धन बनाने की यह मूल्य श्रृंखला पर्यावरण संरक्षण और विदेशी मुद्रा दोनों अर्जित कर रही है। वैश्विक नारियल कॉयर बाजार का मूल्य 2025 में 1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 12,000 करोड़ रुपये) आंका गया है, जिसमें भारत का वैश्विक उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में बिना मिट्टी की खेती में कोकोपीट की बढ़ती मांग के कारण निर्यात में सालाना 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जिसमें चीन (37 प्रतिशत) और अमेरिका (24 प्रतिशत) सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं, इसके बाद नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्पेन का स्थान आता है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु में नारियल के कचरे से धन उत्पन्न करने की कहानी बड़े पैमाने पर साकार हो रही है, जहां प्रतिदिन 150-300 मीट्रिक टन कच्चे नारियल का कचरा उत्पन्न होता है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केरल के कोच्चि और तिरुवनंतपुरम से लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे तक नारियल पानी की भारी खपत ने शहरी स्थानीय निकायों और निजी कंपनियों को नारियल के छिलके के प्रबंधन के लिए समर्पित केंद्र विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। मैसूर और मदुरै ने नारियल के कचरे का 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण करके एक मिसाल कायम की है, जबकि ओडिशा के पुरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों ने मंदिर से उत्पन्न नारियल के कचरे को संसाधित करने के लिए विशेष सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित की हैं - यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी छिलका पीछे न छूटे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान छत्तीसगढ़ केंद्र में राजभाषा हिंदी कार्यशाला आयोजित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) में 30 दिसंबर को राज्य केंद्र एवं जिलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजभाषा नीति एवं नियम विषय पर राज्य स्तरीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना तथा केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।

कार्यक्रम में मुख्यालय से पधारे अजय मधुकर जोशी, उप महानिदेशक एवं समूह प्रमुख (राजभाषा) तथा राजेंद्र कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ निदेशक का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ ऋषि कुमार राय, उप निदेशक (आईटी) एवं हिंदी अधिकारी द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ निदेशक ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजभाषा हिंदी की नीति, नियमों एवं उनके अनुपालन की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यालयीन कार्यों, पत्राचार, ई-ऑफिस तथा तकनीकी दस्तावेजों में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को राजभाषा नियमों से अवगत कराया।

इसके पश्चात अजय मधुकर जोशी, उप महानिदेशक ने संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उपसमिति के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र द्वारा राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में किए गए कार्य सराहनीय हैं।

उन्होंने समिति द्वारा राज्य केंद्र, रायपुर को प्रदत्त प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा हिंदी में किए जा रहे कार्यों को शत-प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम में तेज नारायण सिंह उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी ने कार्यशाला को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया। उन्होंने अतिथि वक्ताओं के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में पी. रामाराव, वरिष्ठ निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कार्यशाला में सहभागिता करने वाले राज्य केंद्र एवं जिलों से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार जताया।

कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट से शेयरधारक किसानों की आय में बड़ा उछाल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। माँ दंतेश्वरी मक्का सहकारी समिति कोण्डागांव द्वारा संचालित एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी क्षेत्र के शेयरधारक किसानों के लिए आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम साबित हो रहा है। प्लांट से जुड़े किसानों को मक्का विक्रय पर बाजार भाव की तुलना में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

एथेनॉल प्लांट के संचालन के बाद समिति द्वारा शेयरधारक किसानों से प्राथमिकता के आधार पर मक्का की खरीद की जा रही है। इस वर्ष भी किसानों को मक्का का बेहतर मूल्य देकर उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में खुले बाजार में मक्का का भाव 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि एथेनॉल प्लांट कोकोड़ी द्वारा शेयरधारक किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की आकर्षक दर पर मक्का की खरीद की जा रही है। इससे किसानों को बाजार भाव की तुलना में सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। बाजार भाव 1600 रूपए प्रति क्विंटल है, जबकि प्लांट दर 2400 रूपए प्रति क्विंटल है, अतिरिक्त लाभ 800 प्रति क्विंटल है। उदाहरण के तौर पर 40 क्विंटल मक्का विक्रय पर किसान को कुल अतिरिक्त आय 32 हजार रूपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। स्थानीय किसानों ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जुड़ने के बाद खेती अधिक लाभकारी बनी है। एक किसान ने कहा, 800 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती में उत्साह बढ़ा है।

कुलपति ने किया नेहरू पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित टेबल कैलेंडर का विमोचन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने आज यहां नेहरू पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित टेबल कैलेंडर 2026 का विमोचन किया।

इस कैलेंडर में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों को सुरूचिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय रापयुर की अधिष्ठाता एवं नेहरू पुस्तकालाध्यक्ष डॉ. आरती गुहे, सहायक पुस्तकालाध्यक्ष माधुरी गौतम, कृषि महाविद्यालय रायपुर के तकनीकी अधिकारी डॉ. रामा मोहन सावू, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय नैयर सहित नेहरू पुस्तकालय के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लोगों के घर सौर ऊर्जा से रोशन

अब तक 900 से अधिक लोगों ने अपने घर की छत पर लगवाए सोलर पैनल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अब लोगों के घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहे हैं। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि एवं बिजली बिल से मुक्ति मिलने से सोलर पैनल लगवाने जिले के हितग्राही काफी उत्साहित हैं।

बलौदाबाजार जिले के लोगों में इस योजना को लेकर उत्साह इतना प्रबल है कि 10 हजार से अधिक परिवारों ने अब तक पंजीकरण कराकर सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में अपना सशक्त संकल्प व्यक्त किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जिले के बदलते सोच और जागरूकता का प्रतीक है।इसी प्रतिबद्धता और प्रशासनिक सक्रियता का परिणाम है कि 900 से अधिक घरों की छतों पर सोलर रूफ्टॉप प्लांट स्थापित हो चुके हैं। ये परिवार आज मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त कर न केवल आर्थिक बचत कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी सार्थक योगदान दे रहे हैं।इस योजना की पारदर्शिता और त्वरित लाभ से योजना के प्रति आम नागरिकों का भरोसा और मजबूत हुआ है तथा सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर दीपक सोनी की निगरानी में ऊर्जा आत्मनिर्भरता का यह अभियान जिले में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सीएसपी डीसीएल के अधिकारियों द्वारा वेंडर एवं हितग्राहियों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

मंत्री राजवाड़े ने बालिकाओं को साइकिल वितरण कर बढ़ाया उत्साह

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बालिकाओं का सशक्तिकरण ही सशक्त राज्य और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। वे भारतीय स्टेट बैंक, बैरन बाजार रायपुर द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आयोजित बेटी बचाओ अभियान के तहत शासकीय विद्यालयों की बालिकाओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए संबोधित कर रही थीं।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को साइकिल वितरित कर उन्हें शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि साइकिल जैसी सुविधाएँ बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इससे स्कूल आने-जाने में सुविधा होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और ड्रॉपआउट की समस्या में कमी आती है। मंत्री राजवाड़े ने भारतीय स्टेट बैंक के इस सामाजिक सरोकार की सराहना करते हुए कहा कि जब शासकीय योजनाओं के साथ बैंक एवं अन्य संस्थाएँ ष्टस्क्र के माध्यम से जुड़ती हैं, तो समाज में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। राज्य सरकार बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बैंक के अधिकारीगण, विद्यालयों के शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्राएँ उपस्थित रहीं। साइकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से कुलेश्वरी एवं लकेश निषाद का दाम्पत्य जीवन हुआ सशक्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य शासन के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में समाज के कमजोर एवं विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के कल्याण हेतु प्रभावी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांग दम्पत्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

योजना के अंतर्गत जिला गरियाबंद के छुरा विकासखंड स्थित ग्राम कुटेना, पोस्ट पाण्डुका निवासी कुलेश्वरी निषाद एवं उनके पति लकेश निषाद को लाभान्वित किया गया है। श्रीमती कुलेश्वरी निषाद (उम्र 34 वर्ष) 45 प्रतिशत अस्थिबाधित हैं, जबकि उनके पति लकेश निषाद (उम्र 24 वर्ष) 40 प्रतिशत श्रवण बाधित हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत दंपत्ति को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर प्रदाय की गई।

प्राप्त सहायता राशि से इस दम्पत्ति ने अपने दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ आधार दिया है। आज श्रीमती कुलेश्वरी एवं श्री लकेश निषाद किसी पर आश्रित नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ सुखमय एवं सम्मानजनक जीवन यापन कर रहे हैं। योजना से मिली सहायता ने न केवल आर्थिक संबल प्रदान किया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया और समाज में सम्मान की भावना को सुदृढ़ किया है।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना राज्य शासन की समावेशी एवं जनकल्याणकारी सोच का सशक्त उदाहरण है, जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

खास खबर

कोरबा में 10 चालकों ने तोड़ा नियम, हुई कार्रवाई

कोरबा। न्यू ईयर से पहले हर तरफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। नियम कायदे बताने के साथ वाहन चालकों पर एक्शन जारी है। कटघोरा में पुलिस ने 10 चालकों पर नियम तोड़ने के मामले में कार्रवाई की। कहा गया कि इस अभियान में कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कटघोरा में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 10 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने न सिर्फ जुर्माना लगाया, बल्कि सभी को सख्त हिदायत दी कि नए साल की रात किसी भी तरह की लापरवाही, हुड़दंग या कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने बताया कि 31 दिसंबर और नववर्ष के अवसर पर यदि कोई व्यक्ति हंगामा करता है, नशे में वाहन चलाता है या शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सीधे जेल भेजा जाएगा। संचालन में नियमों का पालन अनिवार्य होगा तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या झगड़े की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांजगीर में गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण थाना पुलिस ने नए साल के प्रथम दिन ही दो आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर को नववर्ष में शिवरीनारायण पुल चौक मेनरोड पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था दो व्यक्ति एक मोटर सायकल एचएफ डिलक्स में पिठ्ठू बैग में बीच में रखकर अवैध गांजा लेकर शिवरीनारायण कि ओर आने वाला है कि सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में थाना शिवरीनारायण पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया, मौके पर आरोपी के कब्जे से 2 किलो 20 ग्राम कीमती 18000/रुपये, नगदी रकम 7100 एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जुमला कीमती 70100/रूपये को बरामद किया जाकर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 20 (बी), 29 एन.डी.पी. एस. एक्ट पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

बलरामपुर में 38 लीटर अवैध मदिरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। बलरामपुर जिले में अवैध मदिरा के भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने चौकी रघुनाथनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोरही में कार्रवाई करते हुए कुल 38.07 लीटर अवैध मदिरा जब्त की है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ग्राम जोरही निवासी संदीप कुमार के कब्जे से उत्तरप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु निर्मित बियर 6.50 लीटर, विदेशी मदिरा 2.37 लीटर, देशी मदिरा 4.20 लीटर तथा महुआ शराब 25 लीटर, कुल 38.07 लीटर मदिरा जब्त की गई। मामले में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। नागरिकों से अवैध मदिरा से संबंधित सूचना आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07831-299241 अथवा टोल फ्री नंबर 14405 देने की अपील की है।

80 बोरी धान, तहसीलदार ने रास्ते में रुकवाकर पकड़ा

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड अंतर्गत अवैध धान परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया ने बुधवार को ग्राम गौरीपुर मार्ग पर पिकअप लादकर ले जाया जा रहा धान देखा। अवैध होने की आशंका पर उन्होंने पिकअप को रुकवाकर जांच की। इस दौरान धान अवैध पाया गया। वाहन चालक नंदलाल सिंह द्वारा धान के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। पूछताछ में धान के अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर मौके पर ही 80 बोरी धान सहित पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया।

आबकारी-विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

6 लाख से ज्यादा की ठगी, शातिर ने पांच लोगों को बनाया शिकार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साढ़े 6 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यहां ओमकुमार सिन्हा नाम के युवक ने खुद को प्रभावशाली व ऊंची पहुंच बताकर युवकों और उनके परिचितों को आबकारी विभाग व शराब दुकान में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। जितना ज्यादा ऊंची पोस्ट उतना ज्यादा पैसा कहकर झांसे में लिया था। झांसे आए युवकों ने उस भरोसा किया और रुपए दे दिए। जब काम नहीं हुआ तो ठगी का अहसास हुआ। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला धमधा थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, धमधा के सोनकर पारा के रहने वाले घनश्याम सोनकर (31) ने 1 जनवरी 2026 को प्रार्थी थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि राजनांदगांव के रहने वाले ओमकुमार सिन्हा ने उसे और उसके परिचितों को आबकारी विभाग व शराब दुकान में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था। आरोपी ने कहा था कि उसकी विभाग में अच्छी पकड़ है और कुछ ही समय में नौकरी लग जाएगी। जिसके झांसे में आकर प्रार्थी और उसके परिचितों ने अलग-अलग माध्यमों से उसे रकम दी।

पांच युवकों से लिए साढ़े 6 लाख रुपए

रिपोर्ट के अनुसार, शुभम सोनकर से 1 लाख रुपए, गजेंद्र सोनकर से 90 हजार रुपए, प्रियांश सोनकर से 12 हजार रुपए और हेम सिंह साहू से 1 लाख 20 हजार रुपए फोन-पे व स्कैनर के माध्यम से दिए गए। इसके अलावा, प्रियांश सोनकर से 1 लाख 8 हजार रुपए नकद, गजेंद्र सोनकर से 30 हजार रुपए नकद और नागेश नामक व्यक्ति से 37 हजार रुपए नकद लिए गए।

इस प्रकार ओमकुमार सिन्हा ने कुल 6 लाख 51 हजार 817 रुपए ले लिए। इसके बाद नौकरी के लिए युवकों को घुमाता रहा और बार बार अलग अलग बहाने बनाता रहा।

नौकरी नहीं मिली तो थाने में दर्ज कराई शिकायत

काफी समय बीत जाने के बाद भी जब न तो नौकरी लगी और न ही रकम वापस की गई, तब पीड़ितों को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। इसके बाद घनश्याम सोनकर ने थाना धमधा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी ओमकुमार सिन्हा उर्फ ओमप्रकाश (31 साल) को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेने और धोखाधड़ी करने का अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कारोबारी भाई के हत्यारे को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

दो साल पुराने मामले में हुआ फैसला, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी थी तीन गोलियां

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के बहुचर्चित कारोबारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करोड़पति बिजनेसमैन ने 2 साल पहले अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी शादी नहीं होने से नाराज था और शराब का भी आदि था। सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने पूरे घटनाक्रम और सबूतों को रखा।आरोपी के खिलाफ हत्या और अवैध तरीके से पिस्टल रखने की बात साबित हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

दरअसल यह पूरा मामला 25 फरवरी 2024 का है। पीयूष झा अपने छोटे भाई पराग के साथ ही रहता था। दोनों ड्रोन बनाने की कंपनी चलाते थे। घटना की रात दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पराग ने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया। इससे तैश में आकर पीयूष ने कबर्ड से पिस्टल निकाली और 3 गोलियां अपने ही छोटे भाई पर चला दी। पराग जमीन पर गिर पड़ा और पूरे फर्श पर खून बिखर गया। इसके बाद पीयूष ने मां को वीडियो कॉल कर लाश दिखाई और कॉल डिस्कनेक्ट कर भाग गया। मां इनसे अलग कैपिटल होम कॉलोनी में रहती थी। उसने पुलिस को फोन किया। विधानसभा थाने की एक टीम देर रात घटनास्थल पर पहुंची। दूसरी टीम ने शहर में नाकेबंदी कर पीयूष की तलाश शुरू की। शहर में तुरंत नाकेबंदी की गई आरोपी के कार और मोबाइल नंबर के लोकेशन से उसे डीडीनगर इलाके में पकड़ा गया। जानकारी मिली कि आरोपी नशे का आदी था। घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली गई। पिस्टल का लाइसेंस भी नहीं था। थाने में पूछताछ में पराग ने बताया कि वह पिस्टल बिहार से लेकर आया था।

ड्रोन कंपनी के स्टार्टअप के लिए नौकरी छोड़ी थी आरोपी ने

भाई को गोली मारने वाले पीयूष ने रायपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। पीयूष झा एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। उसने छात्रावास अधीक्षक की नौकरी में सिलेक्शन हासिल किया मगर ड्रोन कंपनी के स्टार्टअप के लिए नौकरी छोड़ी। 45 हजार रुपए से ड्रोन बनाने की शुरुआत करने वाले पीयूष का कारोबार दो साल में ही 3.50 करोड़ तक पहुंच गया। इसके बाद उसने काम में अपने भाई पराग को शामिल किया। जानकारी के मुताबिक, पर्सनल लाइफ में पीयूष डिप्रेस रहता था। उसकी एक बार शादी भी टूट गई थी, वो शराब पीने लगा था। पीने की लत की वजह से ही दोनों भाइयों में विवाद होता था। इस कांड के पीछे भी वजह शराब पीने के बाद हुआ झगड़ा ही था।

दोनों भाई मिलकर करते थे काम

आरोपी पीयूष को रेलवे ने पटरियों की निगरानी का काम दिया था। प्रदेश में तैनात आरपीएफ, बीएसएफ और स्टेट पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते उन्हें ड्रोन बनाने का जिम्मा दिया था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी दोनों भाई ड्रोन सर्विस दिया करते थे। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बड़े भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफहत्या और अवैध तरीके से पिस्टल रखने की बात साबित हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

निजी कंपनी के जीएम से मारपीट, कई कामगारों पर गैर जमानती अपराध दर्ज

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। एसईसीएल दीपका क्षेत्र में कलिंगा कॉरपोरेशन (केसीसी) डेको कंपनी को दीपका खदान क्षेत्र में ओबी खनन का ठेका दिया गया है। कंपनी के कामकाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए दीपका माइंस क्षेत्र में साइट ऑफिस दिया गया है। यहां मजदूरों के छुट्टी को लेकर हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा।

जानकारी के अनुसार कंपनी के जीएम एवं प्रोजेक्ट इंचार्ज महेश कुमार और कर्मचारियों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि नियोजित कर्मचारियों ने प्रोजेक्ट मैनेजर महेश बाबू पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। घटना की खबर मिलते ही दीपका पुलिस और सीआईएसएफ टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रोजेक्ट मैनेजर महेश कुमार की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपका पुलिस ने आरोपियों के खिलाफअपराध दर्ज कर लिया है। केसीसी कंपनी के एल एंड आर हेड (जीएम)विकास दुबे ने बताया कि छुट्टी के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से तूल दे दिया। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर पर कुछ हमला कर दिया और उन पर मिट्टी का गमला भी फेंका गया।

घटना में ऑफिस की खिडकी टूटने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं कंपनी के मजदूरों ने बताया कि सोमवार को दीपका में छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें कुछ मजदूर छुट्टी लेकर शामिल हुए थे।

बाद में लौटने पर उनकी हाजिरी काट दी गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। मजदूरों का आरोप है कि महेश कुमार का व्यवहार मजदूरों के प्रति ठीक नहीं रहता, जिससे आक्रोश बढ़ा। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की जांच जारी है।

नए साल में नागरिकों को वापस मिले 100 गुम हो चुके मोबाइल फोन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की उपस्थिति में गुरूवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर कोरबा में शहर और दूरस्थ अंचलों से गुम हुए मोबाइल को साइबर सेल द्वारा ट्रेस किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम में ऐसे सभी 100 मोबाइल को वापस लौटाया गया।

खोई हुई वस्तुओं को लौटाना सिर्फ़ एक प्रक्रिया नहीं—यह नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और उनके विश्वास को लगातार सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत योगेश जैन, पार्षद अशोक चावलानी भी उपस्थित रहे।

अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 31 दिसम्बर 2025 को गस्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी गीतेश कुमार देशलहरे स्थान यादव मोहल्ला बोरसी भाटा के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत 12 नग प्लास्टिक बोतल बॉम्बे स्पेशल व्हिस्की (750 एमएल) एवं आरोपी एवं एवन निषाद, पिता त्रिभुवन निषाद उम्र 27 वर्ष ग्राम ननकट्टी के

कब्जे से 50 नग पाव देशी मदिरा शोले मसाला कुल मात्रा 18 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 10760 रूपये है तथा एक हीरो होंडा स्प्लेन्डर वाहन क्रमांक सीजी 04 0976 जिसका बाजार मूल्य लगभग 30,000 रूपये, कुल कीमत लगभग 40760 रूपये जप्त किया गया।

मौके पर आरोपी के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है।

इस प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल, प्रियंक ठाकुर, भोजराम रत्नाकर, आबकारी मुख्य आरक्षक भरथरी, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की एवं ड्राइवर दीपक राजू, प्रकाश राव एवं धनराज का योगदान रहा।

रायपुर रिंग रोड पर ट्रक हादसा : अधेड़ की मौत, गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के रिंग रोड स्थित गोंदवारा इलाके में हुए सड़क हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मौके पर ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के मोहल्ले गोगांव से बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल और फिर थाने पहुंच गए।

आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुढ़ियारी थाने का घेराव कर आरोपी ट्रक चालक की तत्काल गिरफ्तारी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को

मुआवजा देने की मांग की। घटना गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

मृतक के साले रोहित बागड़े ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7 बजे उनके जीजा काम खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया था, लेकिन मृतक स्थानीय निवासी होने के कारण बड़ी संख्या में परिचित और मोहल्लेवासी भी वहां पहुंच गए, जिससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। थाना प्रभारी भेखलाल चंद्राकर ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने संबंधित ट्रक को जब्त कर लिया है तथा फरार चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया।

अवैध पैंगोलिन तस्करी का भंडाफोड़, स्कॉर्पियो छोड़कर फरार हुए वन्य जीवों के तस्कर

श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। बस्तर जिले के दरभा थाना पुलिस ने तीरथगढ़ चौक पर वाहनों की नियमित जांच के दौरान एक वाहन से संरक्षित वन्य जीव पैंगोलीन बरामद किया है। वहीं वाहन सवार पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गये।

मिली जानकारी के अनुसार दरभा थाना पुलिस ने तीरथगढ़ चौक पर वाहनों की नियमित जांच के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोकने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस को देख वाहन सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली जिसमें वाहन से पुलिस ने लगभग 10 किलोग्राम का एक संरक्षित और दुर्लभ वन्यजीव

पैंगोलिन बरामद किया। जिसकी तस्करी वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत गंभीर अपराध मानी जाती है। दरभा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बरामद पैंगोलिन को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मामले में तस्करों के खिलाफ एफ आईआर दर्ज करने के साथ-साथ फरार अपराधियों की खोज के लिए आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। वन विभाग ने कहा कि तस्करों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और पकड़े गए पैंगोलिन को संरक्षित केंद्रों में सुरक्षित रखा जाएगा। वन्यजीवों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और वन विभाग का संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

भोरमदेव कॉरिडोर का भूमिपूजन : सीएम साय बोले-

छत्तीसगढ़ की प्राचीन धरोहर को मिलेगी नई पहचान

श्रीकंचनपथ न्यूज

कबीरधाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने गुरूवार को कबीरधाम ज़िले के भोरमदेव धाम में आयोजित कार्यक्रम में भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए वर्ष की शुरुआत ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य से होना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना राज्य की प्राचीन धरोहर को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है। कबीरधाम जिले के इस भोरमदेव धाम में महादेव शिव की आराधना, अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक साथ दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना का भूमिपूजन किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर शुरुआत नए वर्ष की नहीं हो सकती थी और इस परियोजना के लिए उन्होंने समस्त छत्तीसगढ़वासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भोरमदेव की महत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया।

मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है

भोरमदेव मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरे-भरे वनांचल के बीच स्थित इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। यह केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि हजार वर्षों की साधना, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा भोरमदेव के रूप में की जाती है, जहाँ शैव दर्शन, लोक आस्था और आदिवासी परंपराएँ एक साथ मिलकर भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा यहाँ की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और उन्हें स्वयं कांवड़ियों का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

उन्होंने उल्लेख किया कि धार्मिक आस्थाओं में यहाँ भगवान राम को 'भाँचा राम' या 'वनवासी राम' के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उनके वनवास के लगभग 10 वर्ष दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है तथा रेल और हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचना सरल होगा और पर्यटन को नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 7.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों को नई दिशा मिलेगी।

पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक : गजेन्द्र सिंह

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भोरमदेव महोत्सव स्थल पर कॉरिडोर के भूमिपूजन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कबीरधाम जिले सहित पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को धरातल पर उतारते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है और आज प्रदेश नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे देश के नागरिकों में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि भारत को कमजोर करने वाली किसी भी ताकत या षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध लिए गए कठोर निर्णयों ने देश की सुरक्षा नीति को नई मजबूती प्रदान की है।

भोरमदेव का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल और छेरकी महल ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण भव्य शिल्पाकृतियाँ खजुराहो की कला से तुलना योग्य हैं। नागवंशी शासनकाल में निर्मित नागर शैली की यह अद्वितीय वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। यह स्थल न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय इतिहास, कला और सामाजिक जीवन का सशक्त साक्ष्य भी है। महाशिवरात्रि पर यह स्थान प्रमुख तीर्थ के रूप में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जहाँ आदिवासी परंपराओं और शैव प्रथाओं का अनोखा संगम दिखाई देता है। मड़वा महल, जिसका संबंध विवाह मंडप से माना जाता है, तथा छेरकी महल की दीवारों पर अंकित वन और नदी से जुड़ी आकृतियाँ प्रकृति-निष्ठ जीवनदर्शन को दर्शाती हैं।

धर्म और अध्यात्म के साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र

सीएम ने कहा कि भोरमदेव का यह संपूर्ण क्षेत्र धर्म और अध्यात्म के साथ-साथ पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, जिसे वर्तमान सरकार व्यापक रूप से विकसित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को संरचनात्मक मजबूती मिली है। नई पर्यटन नीति एवं होम-स्टे पॉलिसी के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा सहित छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानीय उत्सवों ने प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ केवल मंदिरों और स्थापत्य तक सीमित नहीं हैं; बल्कि नाचा परंपरा, 13 पारंपरिक वाद्ययंत्र, लोकनृत्य और गीत हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्पण हैं।

सुशासन का प्रभाव आज देश-दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सुशासन का प्रभाव आज देश-दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। सड़कों, पुल-पुलियों एवं अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल, बिजली, बैंक खाता और रोजगार जैसी सुविधाएं गरीबों के घर-घर तक पहुंच रही हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि भोरमदेव मंदिर लगभग एक हजार वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और इस कॉरिडोर निर्माण के माध्यम से आने वाले हजार वर्षों तक इसे संरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोरमदेव मंदिर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी विशेष आस्था का केंद्र रहा है और यह परियोजना उनके कार्यकाल की स्मृति के रूप में कबीरधाम जिले को एक नई पहचान देगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह वर्ष परिवर्तन का वर्ष है और भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प में 140 करोड़ देशवासी सहभागी बनें।

यहां के विकास के लिए लगातार किए जा रहे प्रयास : डिप्टी सीएम शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लगातार क्षेत्र का दौरा कर यहां के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चैत्र माह के तेरहवीं तिथि को भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, पिछले वर्ष जब स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के लिए हमने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से निवेदन किया था और भोरमदेव महोत्सव के दिन हमें स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी और आज भूमिपूजन भी सम्पन्न हो गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भोरमदेव की तरह ही आस्था का केंद्र माने जाने वाले पंचमुखी श्री बूढ़ा महादेव मंदिर का भी अब विकास किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू, सांसद संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल, राज्य कृषक कल्याण परिषद् के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कच्ची झोपड़ी से पक्के आशियाने तक भरोसे और सम्मान का नया घर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सरकारी योजनाएँ जब ज़मीन पर उतरती हैं, तो वे सिर्फआँकड़े नहीं बदलतीं, बल्कि ज़िंदगियाँ संवारती हैं। ऐसा ही एक जीवंत उदाहरण जिला बेमेतरा के जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ग्राम पंचायत खम्हरिया (एम) के निवासी रेवा राम साहू हैं, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का नया सवेरा लेकर आया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने श्री साहू और उनके परिवार को वह पक्का आशियाना दिया, जिसकी उन्होंने वर्षों तक केवल कल्पना ही की थी। यह मकान आज उनके लिए ईंट-पत्थर की संरचना भर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, विश्वास और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री आवास मिलने से पहले श्री रेवा राम साहू अपने परिवार के साथ एक अत्यंत जर्जर कच्चे मकान में रहने को विवश थे। बरसात के मौसम में छत से टपकता पानी, दीवारों में सीलन और सांप-बिच्छुओं का डर बना रहता था। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पक्का मकान बनवाना उनके लिए एक दूर का सपना था। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में आशा की मजबूत नींव बनकर सामने आई। जैसे ही पहली किस्त की राशि बैंक खाते में प्राप्त हुई, उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। शासन की पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध सहायता से आज उनका पक्का मकान पूर्ण रूप से तैयार है। आज श्री साहू का परिवार एक मजबूत और सुरक्षित पक्के मकान में रह रहा है। यह घर उनके लिए स्थायित्व, शांति और आत्मविश्वास का आधार बन गया है।

रेवा राम साहू कहते हैं कि यह सिर्फएक घर नहीं है, यह हमारे सपनों और आत्मसम्मान की छत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरे पूरे परिवार का जीवन बदल दिया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जनकल्याणकारी सोच के कारण ही गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास का सपना साकार हो पा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का किया लोकार्पण

23 से 25 जनवरी तक आयोजित होगा रायपुर साहित्य उत्सव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर साहित्य उत्सव की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहेब तथा छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा उपस्थित थे।

उल्लखेनीय है कि रायपुर साहित्य उत्सव 23 से 25 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। साहित्य उत्सव में देशभर के प्रख्यात साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, पत्रकारों, समीक्षकों एवं पाठकों की सहभागिता होगी। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति, सृजनात्मक लेखन, प्रकाशन जगत, युवा साहित्य तथा नई पीढ़ी के रचनाकारों से जुड़े विषयों पर विविध सत्र आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री साय ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा कि रायपुर साहित्य उत्सव छत्तीसगढ़ की साहित्यिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उत्सव लेखक और पाठक के बीच नए संवाद का सशक्त मंच बनेगा तथा युवा पीढ़ी में पढ़ने और लिखने की प्रेरणा जागृत करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती लोकसाहित्य, लोककथाओं और समृद्ध मौखिक परंपराओं की धरोहर रही है। ऐसे में रायपुर साहित्य उत्सव राज्य की इस सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का सुअवसर बनेगा।

वर्ष 2026 'महतारी गौरव वर्ष' : मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित - मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नूतन वर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने ऑडियो संदेश में सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जो मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण को समर्पित रहेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में महतारी का स्थान सर्वोच्च है। नारी शक्ति त्याग, संस्कार, श्रम और नेतृत्व की प्रतीक है। महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से समाज के सभी क्षेत्रों में मातृशक्ति के योगदान को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य ने नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की हैं। इस विकास यात्रा में मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महतारी गौरव वर्ष के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में और अधिक सशक्त होकर आगे आएँगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के सहयोग से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और अधिक गति और सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण को अपने आचरण और जीवन का मूल मंत्र बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी मिलकर वर्ष 2026 को नारी सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास का सशक्त प्रतीक बनाएं। यही नया छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का साझा संकल्प है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए समृद्धि, शांति और उन्नति की मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के लिए मशाल गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी

फरवरी में छत्तीसगढ़ में होगा आयोजन, देशभर के जनजातीय खिलाड़ी 7 खेलों में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स के प्रचार-प्रसार के लिए मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के प्रचार-प्रसार के लिए यह वाहन राज्य के सभी जिलों में जाएगी। आयोजन के शुभंकर मोरवीर, थीम-सांग और मशाल के साथ प्रदेशभर में घूम-घूमकर यह लोगों को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की जानकारी देगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित अपने शासकीय निवास कार्यालय से मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव का विषय है कि देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार तथा केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले माह फरवरी में होने वाले इस आयोजन के बारे में लोगों को जानकारी देने आज मशाल गौरव यात्रा को रवाना किया गया है।

खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल 7-8 जनवरी को

खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में सात खेलों को शामिल किया गया है। इनमें हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और वेट-लिफ्टिंग शामिल हैं। इन खेलों में छत्तीसगढ़ की ओर से भागीदारी करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए आगामी 7 जनवरी और 8 जनवरी को ट्रायल का आयोजन किया गया है। बिलासपुर स्थित स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में तीरंदाजी, तैराकी और एथलेटिक्स के लिए ट्रायल प्रक्रिया आयोजित की गई है। लिए ट्रायल रायपुर के स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम कोटा में होंगे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950